HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-30 नवम्बर, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल,
वर्ष 2/ अंक 33/ पृष्ठ: 16
मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com सफलता के लिए सार्थक प्रयास ही उपलब्धि की प्रथम सीढ़ी है..... डॉ0 एल सी शर्मा

THE ONLY INITIATIVE THAT COVERS ALL 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

दिल्ली के दिल प्रदूषण से सहमें-अघोषित आपातकाल

पराली जलाना किसानों की मज़बूरी तो आम लोगों के लिए ख़तरा

आईआईआरडी की पहल, हम देंगे समाधान

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

पर्यावरण संतुलन और स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल 2014 में शपथ लेने के साथ ही शुरु हो गई थी। पूरा भारत संपूर्ण स्वच्छ हो, प्रदूषण से मुक्त समाज का सपना तो देखा लेकिन आज देश में राजधानी दिल्ली का प्रदूषण इसे खुली चुनौती दे रहा है और इसे हरियाणा और पंजाब में किसानों के खेतों में जलाई जा रही पराली से जोड़कर समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई। लेकिन समस्या के बाद समाधान अभी भी मिल नहीं पा रहा है। किसान अगर पराली नहीं जलाते हैं तो अगली फसल को नहीं लगा सकते हैं। अन्य कोई विकल्प उनके पास नहीं हैं। पराली को जलाने के बाद बेहद ही ख़तरनाक धुंआ पर्यावरण को दूषित करता हुआ दिल्ली में जमा हो जाता है। इस पर्यावरणविद बहुत चिंतत हैं और सरकार के माथे पर भी रेखाऐं पड़ गई हैं। क्योंकि अब यदि इसका निदान नहीं हो पाता है तो यह एक गंभीर चुनौती बन जाएगी और सैंकड़ों बीमारियों का घर भी। दिल्ली में एक समय में तो सांस लेना तक भी मुश्किल हो गया और आपातकाल जैसे हालात हो गए। स्कूलों और संस्थानों में अवकाश करके घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। इससे लोगों के जीवन के साथ-साथ पर्यटन आदि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी) ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या के निदान हेतु पहल की है। इसके लिए संस्था गेल इंडिया के सहयोग से चंडीगढ़ में पर्यावरण सम्मेलन करने जा रही है जिसमें नगर निगम चंडीगढ़ के साथ-साथ गेल इंडिया, आईआईआरडी, मिशन रीव एवं अन्य संस्थाओं व कॉरपोरेट्स के लोग शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ें ग़ैर सरकारी संगठन एवं लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने व रोकथाम पर मंथन होगा जिसमें विशेष तौर पर हरियाणा व पंजाब में पराली के निदान की बात होगी। आईआईआरडी इस पर एक वृहद योजना के साथ सरकार को अपनी बात बताऐगी। मिशन रीव के अंतर्गत किसानों की पराली को जैविक खाद में बदलेगी तथा इसके लिए योजना तैयार भी की जा चुकी है। सरकार को इससे सम्बन्धित समस्त जानकारी दी जाऐगी। पराली को रीव जैविक खाद में बदला जाएगा तथा इसके लिए रीव की उसी पद्धति का उपयोग किया जाएगा जिससे हिमाचल प्रदेश में किसानों एवं बागवानों को खाद तैयार करने के लिए अपनाया गया है।

संस्था की पहल

- इसके लिए प्लांट की स्थापना की जाएगी।
- रीव जैविक खाद बनाने की पद्धति को उपयोग में लाकर किसानों की पराली को खाद में बदला जाऐगा।
- किसानों की पराली का निदान भी होगा और उसी पराली की खाद खेतों में उपयोग होगी।
- जैविक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
- संबन्धित प्रदेशों और राजधानी दिल्ली को प्रदूषणमुक्त रखने में यह एक अनूठी पहल।

9 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होगा विस्तार

हिमाचल प्रदेश से बाहर भारत भर में प्रशंसा पाकर विदेशों तक में चर्चा का विषय रहा मिशन रीव अब अपनी सेवाओं के साथ हिमाचल प्रदेश के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी विस्तारित होने की प्रक्रिया में हैं तथा इसका ख़ाका तैयार हो चुका है। विधिवत रुप से 9 दिसंबर 2019 को आईआईआरडी सभागार से इसका लोकापर्ण किया जाएगा जिसमें प्रदेश और देश की नामी हस्तियां शामिल हो रही है। इतना ही नहीं संयुक्त राष्ट्र से भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। मिशन रीव ने अपने 12 महत्वपूर्ण प्रभागों के माध्यम से जीवन के आरंभ से पूर्व और अंत के बाद तक की जन सेवाओं को समाहित कर एक नई पहल की है जिसे अब प्रदेश के बाहर भी लॉच किया जा रहा है। मिशन रीव की सेवाओं का लाभ अब बाहरी राज्यों के लोग भी ले पाऐंगे जिसके लिए मिशन रीव ने एक बड़ा और बेहतरीन आईटी सैट्अप तैयार कर लिया है। पारदर्शिता के साथ आम लोगों की समस्याओं को समाधान करने के नायाब फार्मूले के साथ मिशन रीव आज खूब प्रशंसा पा रहा है। प्रदेश और देश में युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ-साथ उनका पलायन रोकना और अपने गांव, पंचायत, खण्ड और ज़िला में ही रोजगार प्रदान करने के प्रति कृतसंकल्प मिशन रीव बाहरी राज्यों में मिल रहे प्रोत्साहन के चलते भी इसे विस्तारित करने की योजना पर काम कर रहा है। 9 दिसंबर को इसके समस्त पहलुओं पर मंथन और चर्चा उपरांत विधिवत रुप से इसे अन्य राज्यों में विस्तार दिया जाएगा। गौरतलब है कि लगभग 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में हज़ारों रोजगार मिशन रीव के माध्यम से पैदा करने का लक्ष्य निरंतर प्रगतिशील है तथा इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रयास जारी हैं।

Exploring Sustainable Eco-friendly Alternatives of Parali Burning

IIRD ENVIRONMENT CONCLAVE

"BIO-WASTE, ENVIRONMENT AND LIVELIHOOD"
AN ORGANISED APPROACH TOWARDS "CLEAN INDIA, GREEN INDIA"
AND
ENVIRONMENT & BIO-LIVING AWARDS 2019

20th November 2019
Tagore Theatre, Sector 18, Chandigarh
Organised by

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
ISO 9001:2015 Certified
INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT

SML ISUZU | हिन्द सेवा संगठन Hind Sewa Sangathan | FLYERS GROUP PVT LTD | IFTI IIRD Foundation for Technology & Innovation | IFSD IIRD Foundation for Sustainable Development

INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT
IIRD COMPLEX, BY-PASS ROAD, SHANAN, SANJAULI, SHIMLA
HIMACHAL PRADESH 171006, INDIA.
PH. +91 177 2640761, FAX : +91-177-2843528, web : iirdshimla.org

IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर | INSTITUTE FOR INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT | MISSION RIEV Ruralising India- Empowering Villages

Quantifying Sustainable Development Goals
Mission RIEV Perspective
9th December 2019
IIRD COMPLEX, BY-PASS ROAD, SHANAN, SANJAULI, SHIMLA
HIMACHAL PRADESH 171006, INDIA.

2019 को बड़ी उपलब्धियों के साथ देंगे विदाई :डॉ0 एल सी शर्मा

आईआईआरडी प्रबंध निदेशक एवं मिशन रीव प्रमुख डॉ0 एल सी शर्मा ने द रीव टाइम्स से बात करते हुए बताया कि पराली से प्रदूषण का संपूर्ण निदान मिशन रीव के अंतर्गत किये जाने की योजना पर कार्य हो रहा है तथा सरकार को इस बाबत 20 नवंबर को चंडीगढ़ में आयोजित हो रहे भव्य कार्यक्रम में विस्तार से बताया भी जाएगा। पराली का निदान ही जैविक खाद में परिवर्तित करने से होगा तथा इससे न वायु प्रदूषण होगा और पराली की खाद बनाकर किसानों को जैविक खेती में भी सहयोग मिलेगा। मिशन रीव के विस्तार को लेकर उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में मिशन रीव के 2 वर्षों की सेवा के बाद अब समय आ गया है कि इसे हिमाचल से बाहर अन्य राज्यों में भी विस्तार दिया जाए। इसके लिए विश्वस्तरीय आईटी सैट्अप के माध्यम से नितांत पारदर्शिता के साथ सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं जिसका लाभ अब बाहरी राज्यों के लोगों को भी मिलेगा। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश-विदेशों से प्रतिनिधि शामिल होंगे जिसमें नीति आयोग के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, पंचायतों के प्रतिनिधियों के अलावा संगठनों एवं अन्य कॉरपोरेट्स से प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं।

आईआईआरडी और मिशन रीव के सौजन्य से

रक्तदान शिविर में 70 से अधिक यूनिट रक्त हुआ एकत्रित

द रीव टाइम्सः हेम राज चौहान

किसी का जीवन यदि आपके रक्त से बच सकता है तो रक्तदान करके हम इसे संभव बना सकते हैं। चौपाल स्टुडेंट ऐसासिएशन के प्रयासों को आईआईआरडी ने मिशन रीव के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के ऐतिहासिक रिज़ मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 90 के लगभग रक्तदाताओं ने रक्तदान करके मानव सेवा में योगदान दिया। रक्तदाताओं में ऐसोसियेशन के कार्यकर्ताओं के अलावा आईआईआरडी, मिशन रीव, हिंद सेवा संगठन के सेवाकर्मियों ने भी भाग लिया और रक्तदान किया। संस्था ने इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता के साथ-साथ मिशन रीव की सेवाओं को भी लोगों से विभिन्न माध्यमों से रुबरु करवाया। इस बाबत बाक़ायदा स्टॉल पर लोगों को मिशन रीव की सेवाओं के प्रति जागरुकता की गई। कार्यक्रम में द रीव टाइम्स समाचार पत्र भी लोगों को उपलब्ध करवाया गया। कार्यक्रम आयोजक चौपाल ऐसोसियेशन के प्रधान ने आईआईआरडी और मिशन रीव का आभार जताते हुए कहा कि संस्था ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित करके युवाओं को न केवल उत्साहवर्धन किया बल्कि मानव सेवा का परिचय दिया है। आईजीएमसी की टीम ने रक्तदान शिविर में सहयोग दिया। प्रबंध निदेशक डॉ0 एल सी शर्मा ने इस अवसर पर द रीव टाइम्स को बताया कि भविष्य में शीघ्र ही आईआईआरडी रक्तदान शिविर आयोजित करेगी जिसमें 1100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मिशन रीव का सहयोग होगा तथा अधिक से अधिक युवाओं को इस पुण्य सेवा में शामिल किया जाएगा। रिज पर आयोजित कार्यक्रम में आईआईआरडी और मिशन रीव की ओर से हेम राज चौहान, डॉ0 के आर शांडिल, नरेन्द्र ठाकुर, अजय, महरीन, सोनू सरकैक, श्रवा और अन्य सेवाकर्मियों ने भाग लिया।

चौपाल स्टुडेंट ऐसोसिएशन के कार्यक्रम को किया प्रायोजित

यमनोत्री में संपूर्ण स्वच्छता के सपने को साकार करता आईआईआरडी

द रीव टाइम्स

सीएसआर यानी कारपोरेट रिस्पॉसिबीलिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने में आईआईआरडी अहम भुमिका निभा रहा है। बात शिक्षा की हो, पिछड़े वर्ग को आगे ले जाने के लिए बनी योजनाओं की हो या जनकल्याण से जुड़ी कोई गतिविधि हो, आईआईआरडी आज हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। अन्य गतिविधियों के साथ आईआईआरडी स्वच्छ भारत अभियान में भी बढ़चढ़ कर अपना योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में आईआईआरडी यमनोत्री में यात्रियों के लिए सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए **गेल इंडिया** के सौजन्य से कई प्रकार के कार्य कर रहा है। यहां यात्रियों को विभिन्न तरह की सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही आईआईआरडी ने स्वच्छता का जिम्मा भी बखूबी संभाला है। इसके तहत यात्रियों को रास्ते में विश्राम करने के लिए सराय निर्माण, बैठने के लिए बैंच, यात्रा मार्ग में कूड़ेदानों को लगाना, खच्चरों के लिए समस्त उचित व्यवस्था करने से लेकर अन्य सुविधाओं को भी प्रदान की गई है। **गेल इंडिया** द्वारा प्रायोजित इस परियोजना में यमनोत्री में यात्रियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की की जा रही है। जानकी चट्टी से यमनोत्री मंदिर तक 5 कि.मी. मार्ग पर इन सुविधाओं में संस्था सेवाएं प्रदान कर रही है। यमनोत्री के मौसम के हिसाब से वहां अत्यधिक ठंड होती है जिसके कारण यात्रियों के अलावा खच्चरों को भी दिक्कत होती है। इसके लिए आईआईआरडी गर्म पानी की समुचित व्यवस्था कर रहा है। आर.ओ. प्रणाली से स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है तथा पानी को गर्म रखने के लिए हीटर भी लगाए गए हैं जो कि टैंक आदि के साथ संबद्ध किए गए हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। खच्चरों के लिए भी पानी की खुरलियों का निर्माण रहा है जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था रहती है। यात्रियों को आवश्यक जानकारी हेतु सहायता कक्षों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें यात्रा संबन्धि एवं अन्य जानकारियों को प्राप्त किया जा सकेगा।

यमनोत्री में स्वच्छता को आधारभूत एवं प्राथमिकता सेवा मानते हुए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शौचालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। ये शौचालय यात्रियों की सुविधा तथा स्वच्छता को बनाए रखने के लिए खोले गए हैं।

इसके अलावा यात्रा मार्ग में बैच और कुर्सियों का प्रबन्ध किया गया है ताकि थकान के बाद यात्रि विश्राम कर सके। इसी प्रकार यमनोत्री में दो स्थान चिन्हित कर वहां यात्रियों के लिए चाय-पान का प्रबन्ध भी संस्था द्वारा किया गया है। यात्रि यहां जलपान करके मिशन रीव के अंतर्गत पौष्टिक स्पिरुलिना के उत्पादों का भी स्वाद ले सकते हैं। इन उत्पादों में स्पिरुलिना बिस्किट और कैपसूल आदि शामिल है। इसके अलावा मौसम के प्रतिकूल होने पर भी यात्रियों के लिए रेनकोट, छतरी आदि की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को दिशा - निर्देश, आवश्यक जानकारी एवं मनोरंजन के लिए व्यवस्थित स्थलों पर एलईडी स्क्रीन को लगाया गया है।

यमनोत्री को स्वच्छ रखने के लिए आईआईआरडी के स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सेवाओं को लिया जा रहा है। यात्रियों द्वारा कूड़ा-कर्कट आदि जो भी यमुना अथवा इसके आस-पास फेंका गया है अथवा फेंका जाता है उसे उठाया जाता है तथा समुचित स्थान पर उसका निदान किया जा रहा है। यात्रियों को प्लास्टिक या अन्य व्यर्थ वस्तुओं को यत्र-तत्र या नदी में न फेंकने के लिए साइन बोर्ड आदि लगा कर जागरुक किया जा रहा है। यात्रियों को अन्य माध्यमों से भी जानकारी दी जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से आईआईआरडी यमनोत्री धाम को यात्रियों के लिए अति सुगम्य, स्वच्छ एवं यात्रा को आनंद में परिवर्तित करने के प्रति संकल्पबद्ध है। **गेल इंडिया** के इस प्रयास को संस्था शतप्रतिशत सफलता के रुप में तीर्थयात्रियों के लिए पूरी करने के लिए प्रयासरत है ।

सफाई के लिए अभियान

यमनोत्री में आईआईआरडी द्वारा गेल इंडिया की वृहद् योजना पर सेवाओं के साथ-साथ स्वच्छता अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है । इसी के तहत यमनोत्री में गेल इंडिया द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा **गेल इंडिया** के पदाधिकारियों के साथ आईआईआरडी की ओर से भी प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा की अगुवाई में शिमला से टीम ने भाग लिया तथा यमुना की सफाई की। गेल इंडिया से जनरल मैनेजर अनूप गुप्ता, कार्यकारी निदेशक प्रसून कुमार, वरिष्ठ अधिकार दीपक कुमार एवं सानु कुमार रजक ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा यमुना के आस-पास भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा के साथ, निदेशक सुषमा शर्मा, फ्लायर ग्रुप के निदेशक व सीईओ आन्नद नायर, आईएफटीआई के सीओओ रंजन मोहंती, आईआईआरडी के कंपनी सचिव अभिमन्यु कवंर और परियोजना अधिकारी आईआईआरडी विशाल शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान के अलावा लोगों को जागरुक भी किया गया।

गेल
GAIL
गेल (इंडिया) लिमिटेड सी एस आर कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता अभियान
IIRD हम जानते हैं गाँव को बेहतर
Implemented by: IIRD – www.iirdshimla.org
Institute for Integrated Rural Development
एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान
हम जानते हैं गाँव को बेहतर

TAKING FURTHER THE SWACHH BHARAT ABHIYAN

IIRD has always believed in sustainable development where humans may benefit and the nature, environment can be protected. Hence, time and again we have propagated the activities that may support the Swachh Bharat Abhiyan.

Providing support to Yamunotri Pilgrims in Uttarakhand under the Swachh Iconic Places via the collaborative effort by IIRD and GAIL India to ensure facilitation of the pilgrims and boost sanitation, cleanliness of the revered environment along the trekking route to Yamunotri.

6 Toilets for better sanitation along the revered trekking route

15 Dustbins installed for cleanliness

2 Bottle Crushers for proper waste management

10 Benches installed for the facilitation of the pilgrims

2 RO water purifiers along with **2** Hot Water stations for the mules

8 Electrical Water Heaters have also been set up **Pilgrims Facilitation Centre** has also been set up

which includes

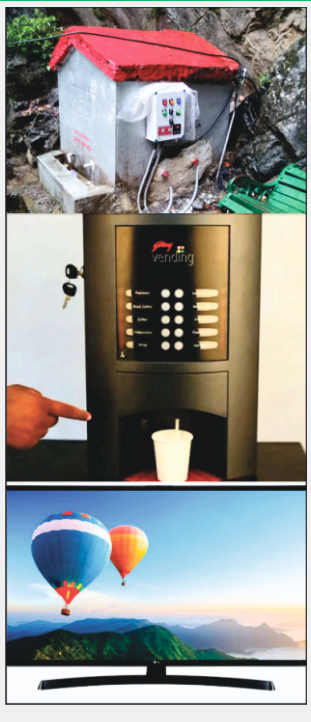

2 Coffee Vending Machines

2 Televisions for the facilitation of the pilgrims

15 Environment Assistants have been appointed to oversee the smooth implementation and success of this programme who have been recruited from the local regions and have been provided with a livelihood skill and a source of earning

पीएमकेवीवाई के छात्रों ने आईआईआरडी सभागार में मनाया बाल दिवस समारोह

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत आईआईआरडी में चल रहे केन्द्र के छात्रों ने बाल दिवस के अवसर पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें आईआईआरडी के सभी सेवाकर्मी शामिल हुए । इस कार्यक्रम में आईआईआरडी की निदेशक सुशमा शर्मा के साथ-साथ समस्त कर्मचारियों और केन्द्र के छात्रों ने भाग लिया । कार्यक्रम में बोलते हुए सुषमा षर्मा ने कहा कि हम शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरुक हों और हर वंचित बच्चे को शिक्षित करने में अपना सहयोग दें । फूलायर ग्रुप के सीईओ आन्नद नायर ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में हम सभी को सहयोग देने की आवश्यकता है । आईएफटीआई के सीईओ रंजन मोहंती ने भी इस अवसर पर कहा कि बच्चों और युवा पीढ़ी को नई ऊर्जा व उत्साह से आगे आकर समाज सेवा में योगदान देना होगा । इस अवसर पर आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ० एल सी शर्मा ने दिल्ली से वीडियो कॉल के माध्यम से सभागार में उपस्थित समस्त छात्रों एवं कर्मचारियों से बात कर अपना संदेश दिया । उन्होंने कहा कि हमें हर पल क़दम दर क़दम आगे बढ़ने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित कर संघर्षरत रहना है । इसी में राष्ट्रनिर्माण की नींव रखी जा सकती है । कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया । कार्यक्रम में सुषमा शर्मा के अलावा आन्नद नायर, डॉ० के आर शांडिल, रंजन मोहंती, प्रवीण मिश्रा तथा अन्य समस्त सहयोगियों ने भाग लिया ।

बच्चों में संस्कार और गुणों का विकास के प्रति सजगता से ही बाल दिवस की अहमियत : सुषमा शर्मा

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

बाल दिवस को मनाने का औचित्य मात्र इतना ही नहीं कि आज चाचा नेहरु का जन्म दिवस है और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे । बल्कि इसको बच्चों में संस्कार और गुणों के निरंतर विकास के प्रति सजगता से देखने की आवश्यकता है । बच्चे हमारे समाज का उज्जवल भविष्य हैं और इन्हीं के कांधों पर हमारे समाज का स्वरुप स्थिरता लिए हुए है । ऐसे में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों में आरंभ से ही इन गुणों का विकास करें ताकि वो एक मज़बूत भारत की नींव रख सके.....ये उद्गार आईआईआरडी की निदेशक सुषमा शर्मा ने शनान, संजौली स्थित मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बाल दिवस समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करने के बाद कहे । मॉडर्न पब्लिक स्कूल शनान में बच्चों एवं अभिभावकों ने अध्यापकों संग बाल दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर निदेशक सुषमा शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि पधार कर बच्चों एवं अभिभावकों से बात की। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि बच्चों पर बोझ न बढ़ा कर उनके मानसिक संतुलन को सही रखने में मदद करें ।

कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन से कविता ठाकुर और अध्यापकों ने भी भाग लिया ।

मुलिंग पुल के निर्माण कार्य से नाखुश मुलिंग पंचायत के लोग : उपप्रधान निर्माण की जांच हो : रवि ठाकुर

द रीव टाइम्स : (सुरेन्द्र सेन)

मुलिंग पुल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। गौर रहे 2016 में साढ़े चार करोड़ से निर्मित पुल 2017 के सर्दियों में टूट कर गिर गया था और जिसे एक बार फिर से ढाई करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ग्रमीणों का आरोप है कि पुल फिर से टेढ़ा ही बन रहा है। मुलिंग पंचायत के उपप्रधान दिनेश भानू ने कहा कि हमारे कहने के बाबजूद भी निर्माण कार्य लगातार जारी है । हमे आशंका है कि कहीं दुबारा यह पुल ढह न जाये । इस पुल से मुलिंग,बरगुल, शिप्टिंग तथा गुआड़ी के लोग पिछले वर्ष चन्द दिनों के लिए जुड़ तो गए थे मगर कुछ ही महीनों में सर्दियों के के यह पुल टूट गया जिसके कारण उक्त गांव वासियों में गहरी नराजगी तथा रोष है। हालांकि विभाग ने इस वर्ष सीजन के अंत तक पुल को दुबारा तैयार करने की बात कही थी मगर हुआ वही जिसकी चिंता थी।पुल के टेढ़े होने से सम्पूर्ण गांव वासियों में रोष फैला है । पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि इस पुल का काम ठीक से नही हो रहा है । उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है ।

आम यातायात के लिये सितम्बर 2020 में खुलेगी रोहतांग सुरंग : मुख्य अभियंता

कामधेनू साबित होगी रोहतांग सुरंग : ब्रिगेडियर मनोज कुमार

द रीव टाइम्स ब्यूरो :(सुरेन्द्र सेन)

रोहतांग सुरन परियोजना के चीफ इंजीनियर विशेष सेवा मैडम बीआरओ के चीफ केपी पुरषोथमन ने कहा कि देश की महत्वपूर्ण रोहतांग सुरंग परियोजना का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह सुरंग आम यातायात के लिये सितम्बर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगी। चीफ इंजीनियर अपने सोलांग मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे । उन्होंने कहा कि रोहतांग सुरंग में सेरी नाले के रिसाब का भी स्थाई समाधान निकाल लिया गया है। उन्होंने बताया जो सेरी नाला करीब पांच वर्षों से भी लंबे समय से तंग कर रहा था,इस बार इसका स्थाई हल निकल गया है।हालांकि इसे समय से पूर्व ही सुनिश्चित किया गया है।अब इस नाले के नियंत्रण में आने से कार्य करने में ओर अधिक तेजी आएगी। बीआरओ का प्रयास रहेगा कि लाहुल के लोग आपदा व विपदा के समय सर्दियो में सुरंग का प्रयोग कर सकें। सिविल वर्क लगभग पूरा कर लिया गया है तथा इलेक्ट्रिक वर्क्स को भी गति दे दी है। सुरंग के उदघाटन बारे पूछने पर उन्होंने कहा कि यह सब उच्चाधिकारी ही तय करेंगे।

लाहुल घाटी के लोगो की सुविधा के लिये बीआरओ ने ओएफसी की लाइन रोहतांग दर्रे से हटाकर रोहतांग सुरंग से कर दी है जिससे अब लाहुल घाटी में दूर संचार सेवा सुचारू हो गई है। घाटी के लोगों की सुविधा को दूसरे चरण में बिजली की 33 केवी लाइन को बिछाने की तैयारी बिजली विभाग के साथ चल रही है। लाइन बिछ जाने से लाहुल घाटी से बिजली आसानी से लाई व पहुंचाई जा सकेगी । उन्होंने कहा कि सुरंग के सफर को सुरक्षित बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोलांग से धूंधी तक 12 एवलांच विरोधी सुरंगे बन रही है। चीफ ने कहा कि सुरंग के दोनों ओर के क्षेत्र को परंपरागत व स्थानीय शैली से विकसित किया जाएगा । उधर रोहतांग सुरंग में विपरीत परिस्थितियों में अपने सेवाएं दे चुके ब्रिगेडियर मनोज कुमार ने कहा कि वे इस सुरंग को कभी भुला नही पाएंगे । ब्रिगेडियर मनोज ने बताया कि यह सुरंग बहुउद्देश्यीय साबित होगी और राष्ट्र विकास की इबारत लिखेगी। दुनिया भर में अपने ही किस्म की यह सुरंग निश्चित रूप में कामधेनू साबित होगी। वहीं लाहुल निवासी राजेश हरकू ने सरकार और बीआरओ का धन्यवाद व्यक्त करते हुए देश के साथ साथ जनजातीय परिवेश के लिए इस सुरंग को मील का पत्थर बताया है । इस अवसर पर सुरंग परियोजना के निदेशक कर्नल परीक्षित मेहरा, लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद कुमार तथा ऑफिसर कमांडिंग कुलदीप के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे ।

अयोध्या : सुप्रीम कोर्ट का फैसला– विवादित ज़मीन पर राम मंदिर बने, मुस्लिमों को मस्जिद के लिए जमीन मिले

द रीव टाइम्स ब्यूरो

134 साल पुराने अयोध्या मंदिर-मस्जिद विवाद पर आख़िर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया । चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया । इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी । शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए । चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब दोगुना है । चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है ।

इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ द्वारा 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया । चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एसए बोबोडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा । सरकार इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन करेगी । साथ ही विवादित ज़मीन से लगभग दोगुणी ज़मीन मस्ज़िद के लिए वैकल्पिक रुप से उपलब्ध करवाने के आदेश भी जारी किए ।

रविवार ने खत्म कर दीं सरकारी कर्मचारियों की चार छुट्टियां, सरकार ने जारी किया शेड्यूल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में अगले साल कर्मचारियों की चार छुट्टियां खत्म हो गई हैं। यह छुट्टियां रविवार के दिन आई हैं, लेकिन चार त्यौहार ऐसे हैं जो सोमवार को आए हैं। ऐसे में कर्मचारी माह के दूसरे शनिवार के साथ तीन दिन लेकर घूमने का कार्यक्रम बना सकेंगे। प्रदेश सरकार ने गुरुवार को वर्ष 2020 छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है।

वैकल्पिक अवकाश 12 रहेंगे। महिलाओं के त्यौहार रक्षाबंधन सोमवार को, करवाचौथ बुधवार जबकि भैयादूज सोमवार को आया है। 26 जनवरी, गुरू गोविंद जयंती, मोहर्रम और दशहरा रविवार को आया है। इसी तरह सोमवार को ईद उल फितर, गुरुनानक जयंती, रक्षा बंधन और भैया दूज सोमवार को आए हैं।

वर्ष 2020 के कलेंडर में 38 अवकाश

वर्ष 2020 के कलेंडर में 38 अवकाश हैं। इसमें सार्वजनिक अवकाश 23, वैकल्पिक 12 और 3 महिलाओं के अवकाश हैं। इसके अलावा डीसी भी अपने जिले में मेले के लिए दो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे।

हिमाचल में उद्यमियों को मनपसंद जमीन मुहैया करेगी सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रदेश सरकार हिमाचल में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए मनपसंद जमीन उपलब्ध कराएगी। सरकारी जमीन के बीच में अगर निजी लोगों की जमीन आती है तो इस पेच को भी सरकार अपने स्तर पर सुलझाएगी । इन्वेस्टर मीट को लेकर उद्योगपतियों के साथ हुए एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई । उद्योग विभाग से लेकर अन्य विभाग जिनसे संबंधित एमओयू हुए हैं, उन विभागों के सचिवों सहित विभागाध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया । प्रदेश सरकार ने निवेश को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियम तैयार किए जा रहे हैं। हिमाचल में लैंड बैंक तैयार किया गया है, जो उद्योगपतियों को दिखाया जाना है।

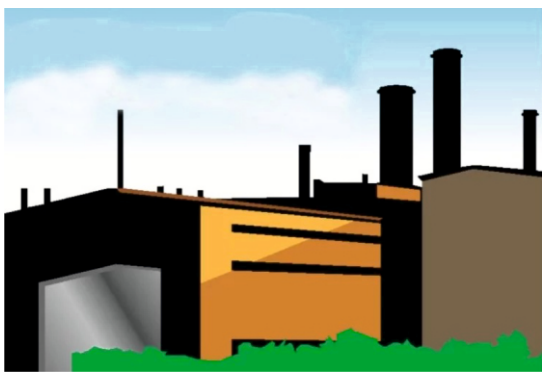

बताया जा रहा है कि चार उद्योगपतियों ने हिमाचल में जमीन देख ली है। इसमें ऊना स्थित मुबारिकपुर के जीतपुर में लगाई जाने वाली ट्रेन के पहिये और एक्सल बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने जमीन देख ली है। यह कंपनी 1100 करोड़ रुपये की लागत से प्लांट स्थापित करेगी। यह उद्योग 50 एकड़ जमीन पर स्थापित होगा।

उद्योगपति ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन

उद्योगपतियों को हिमाचल में उद्योग स्थापित करने के लिए कहां जमीन चाहिए, इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। तीन साल तक उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उद्यमियों को हिमाचल में उद्योग लगाने के लिए पसंद की जमीन दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुबारिकपुर में ट्रेन के पहिये और एक्सल बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों ने जमीन देख ली है।

रोहतांग–लाहुल–स्पीति में बर्फबारी

खराब मौसम ने बढ़ाई कबायलियों की दिक्कतें, रोहतांग दर्रे पर दो फुट ताजा हिमपात दर्ज, सोलंगनाला ने भी ओढ़ी बर्फ की चादर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रोहतांग दर्रे सहित लाहुल-स्पीति में भारी हिमपात दर्ज किया गया है। भारी बर्फबारी के चलते जहां लाहुल का संपर्क मनाली से कट गया है, वहीं स्पीति घाटी को मनाली से जोड़ने वाले काजा-ग्रांफू सड़क पर रफ्तार रुक गई है। ऐसे में खराब मौसम ने जनजातीय जिला के लोगों की दिक्कतें बढ़ा डाली है। जानकारी के अनुसार रोहतांग दर्रे पर हिमपात को दौर शुरू हो गया था, दर्रे पर भारी बर्फबारी के चलते घाटी के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बात यहां मनाली की करें तो मनाली में भी बादलों के बरसने का दौर दिन भर चलता रहा। मनाली के स्नों प्वाइंट सोलंगनाला में भी करीब छह इंच बर्फबारी दर्ज की गई है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

नशाखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के उपायुक्त ने दिए निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

जिले में मादक द्रव्यों के सेवन और मदिरा व्यसन पर रोक के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ 15 नवंबर से किया गया। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह विशेष अभियान पूरे राज्य समेत सोलन में 15 नवंबर से शुरू किया गया है और यह 15 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन-जन को नशाखोरी के विरुद्ध जागरूक कर इस कुरीति का उन्मूलन सुनिश्चित करना है। इस महत्वपूर्ण अभियान की सफलता विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं के आपसी समन्वय पर निर्भर करती है। प्रदेश सरकार ने इस अभियान के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर जिला स्तर पर भेजी है। जिला सोलन में जिला मुख्यालय, उपमंडल एवं आवश्यकतानुसार पंचायत स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपमंडल स्तर पर सभी के सहयोग से अभियान को गति प्रदान करें। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने कहा कि इस अभियान में सभी की भागीदारी अपेक्षित है। सहायक आयुक्त भानू गुप्ता ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

दुधारु पशुओं को चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

जिले में दुधारू गाय और भैंसों को चिह्नित करने के लिए टैग लगाने का काम शुरू हो गया है। अपर बसाल पंचायत के नरेश कुमार के डेयरी फार्म में चार गायों को विशेष प्रकार के टैग लगाकर इसका शुभारंभ किया गया। यह काम केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार की पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य योजना के सूचना नेटवर्क (इनाफ) के तहत किया जा रहा है। उपनिदेशक पशु पालन विभाग डॉ. जय सिंह सेन ने बताया कि योजना के तहत सभी दुधारू गाय और भैंसों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। दुधारु पशुओं को 12 डिजिट के यूनिक पहचान नंबर (यूआईडी) के साथ प्लास्टिक टैग विधि से पहचान की जा रही है। चिह्नित पशुओं के डाटा इनाफ ऐप के डाटाबेस पर अपलोड किया जा रहा है। इस ऐप से

पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का पूरा ब्योरा रखा जा सकेगा। इससे पशुओं की नस्ल को सुधारने में सहायता मिलेगी। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग शिमला से लेकर दिल्ली में बैठकर कहीं भी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग और जरूरी सामग्री दी गई है। उन्होंने सभी पशुपालकों से इस योजना को सफल बनाने की अपील की है।

पंचायत उप चुनाव में 18 पदों पर निर्विरोध चयन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

पंचायती राज उप चुनाव में 18 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। जिले में हो रहे उपचुनाव में 18 पदों पर एक - एक उम्मीदवार के चलते निर्विरोध चयन किया गया। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रमन कुमार शर्मा ने बताया कि सनोली पंचायत के उप प्रधान पद पर एक ही उम्मीदवार है। इसके अलावा ऊना उप - मंडल की नंगड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4, कोटला कलां अपर के वार्ड नंबर 3 व जखेड़ा के वार्ड नंबर 1 में निर्विरोध चुनाव हुआ है। उन्होंने कहा कि हरोली उप मंडल की भदसाली पंचायत के वार्ड नंबर 1 तथा चंदपुर के वार्ड नंबर एक पर भी उम्मीदवार का चयन निर्विरोध हुआ है।

इसके अलावा अंब उप-मंडल की ग्राम पंचायत ज्वाल के वार्ड नंबर-2, नैहरी नौरंगा के वार्ड नंबर 9, लडोली के वार्ड नंबर 5 तथा कुठियाड़ी के वार्ड नंबर 4 में भी चुनाव निर्विरोध हुआ है।

रमण कुमार शर्मा ने कहा कि गगरेट उप मंडल की ग्राम पंचायत मरवाड़ी के वार्ड नंबर 5, मावा सिंधिया के वार्ड नंबर 4, रायपुर के वार्ड नंबर 7 तथा नंगल जरियालां के वार्ड नंबर 7 में उम्मीदवार का चयन निर्विरोध हुआ है। इसके साथ ही बंगाणा उप मंडल की ग्राम पंचायत थाना कलां के वार्ड नंबर 7, टीहरा के वार्ड नंबर 6, बुधान के वार्ड नंबर 3 तथा टकोली के वार्ड नंबर 5 पर भी चुनाव निर्विरोध हुआ है।

नशा मुक्ति अभियान से पहले चिट्टे के साथ दो गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ऊना। पुलिस ने जिला में नशा मुक्ति अभियान शुरू होने से पहले टाहलीवाल के पास दो युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिलाभर में नशा माफिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया है।

पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर गुप्त सूचना के आधार पर दो लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 8.49 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। चिट्टे के साथ पकड़े आरोपियों की पहचान दीपक कुमार पुत्र राज कुमार निवासी हाउस नंबर 177 डीएसईई पुराना नंगल जिला रोपड़ पंजाब के रूप में हुई है। दूसरे आरोपी की पहचान रवि कुमार पुत्र चमन लाल निवासी हाउस नंबर 587 जी ब्लॉक नंगल जिला रोपड़ पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ड्रीम लैंड होटल के पास टाहलीवाल-संतोषगढ़ मुख्य मार्ग पर बाइक सवार युवक दीपक कुमार से 3.42 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी बाइक भी जब्त कर लिया है। इसके अलावा टाहलीवाल पुलिस ने बाथड़ी में हनुमान मंदिर के पास आरोपी युवक रवि कुमार के कब्जे से 5.07 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

गौरतलब है कि पुलिस ने बुधवार को भी ऊना और संतोषगढ़ में पंजाब के दो लोगों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो दिन में चिट्टे के साथ पंजाब के चार आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है।

एसपी दिवाकर शर्मा का कहना है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिले में नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।

दुलैहड़ बाजार की 30 वर्ष पुरानी सड़क की समस्या होगी हल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

क्षेत्र के दुलैहड़ बाजार में 30 वर्ष पुरानी सड़क की समस्या जल्द ही खत्म होने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने जांच रिपोर्ट में पाया कि दुलैहड़ बाजार के पास तालाब के कारण सड़क पर इसका असर पड़ रहा है। इसके साथ सड़क के नीचे चिकनी मिट्टी होने से बरसात में सिलिंग आ जाती थी। इससे सड़क बार-बार नीचे धंस रही थी। इसके लिए विभाग ने सड़क को करीब 3 फीट तक खोद दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए विभाग सड़क के नीचे मोटी पत्थरों की बजरी डाली जाएगी। उसके बाद ही सड़क निर्माण शुरू किया जाएगा। दुलैहड़ बाजार में ट्रक पलटने के हादसे से सबक लेते हुए विभाग ने सड़क पर काम शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बीच बाजार में उतराई के मोड़ पर अनियंत्रित होकर अकसर ट्रक पलट जाते थे। गनीमत रही कि इन हादसों में अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ।

कुछ दिन पहले भी ट्रक सुबह के समय पलट गया था। नेहरू यूथ क्लब के अध्यक्ष नितीश शर्मा ने बताया कि विभाग ने सड़क सुधार को लेकर कवायद शुरू कर दी है। एसडीओ राजेश पाठक ने बताया कि विभाग समस्या

को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से इस सड़क को नए सिरे से तैयार कर रहा है। इसके लिए विभाग ने सड़क को तीन फीट गहरा खोद कर नीचे पत्थरों की मोटी बजरी डाली है। इससे सड़क की सतह मजबूत हो सके और सड़क न धंस सके।

जनमंच में 95 शिकायतों का किया निपटारा

द रीव टाइम्स, ऊना

जनमंच में 95 शिकायतों का निपटारा किया गया। इनमें जनमंच के लिए चयनित 42 शिकायतें अन्य पंचायतों से 31 और 22 प्री जनमंच की शिकायतें शामिल हैं। चलेट की शकुंतला देवी ने आंगनबाड़ी से निकाले जाने पर बहाली की मांग और मकान न बनने की शिकायत की।

इस पर विस उपाध्यक्ष हंसराज ने डीसी और डीपीओ को शीघ्र मामले को सुलझाने के आदेश दिए। इस पर तहसीलदार मनीश चौधरी ने मौके पर ही 15 नबंबर को निशानदेही की तारीख घोषित कर दी। सुरम चंद चलेट ने ट्यूब बेल, इसी गांव के शादी लाल ने रास्ते की मांग, कुलदीप सिंह चलेट ने पानी की निकासी, बलदेव सिंह चलेट ने पुलिया निर्माण कार्य से संबंधित, इसी गांव के संजीव कुमार ने श्मशानघाट को जमीन आवंटित करने, इसी गांव की सोनी देवी ने आंगनबाड़ी में नौकरी और मकान बनवाने की मांग रखी।

जोह के व्यासदेव ने डिस्पेंसरी स्टाफ तैनाती की मांग, मवाकोहलां हरदयाल ने आईआरडीपी में होने के बावजूद मकान न बनने, दौलतपुर चौक के सूबेदार सुशील सिंह ने गलत ढंग से रास्ता निर्माण के चलते घरों में घुस रहे बारिश के पानी की समस्या उठाई। साथ ही रजिस्ट्री के नाम पैसा वसूलने वालों की शिकायत की। मुख्यातिथि हंसराज ने तुरंत जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि हर पटवार खाने पर नंबर अंकित किये जाएं। साथ ही एसडीएम को निर्देश दिए कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य किया जाए। अंबोआ के अंकुश ने चैनेलाइजेशन से संबंधित मांग रखी। चलेट के विकास में रेलवे ट्रेक के निर्माण से ट्यूब वेल से खेतों को सिंचाई में दिक्कत उठाई।

ढाबों पर लोगों को खिलाया जा रहा है तेल से तैयार किया मक्खन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

ढाबों में मक्खन के नाम पर लोगों को मारग्रेन परोसने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने 10 ढाबा मालिकों को नोटिस भेजा है। हिमाचल के सोलन जिला के कसौली में सड़क किनारे ढाबों सहित अन्य स्थानों पर विभाग ने निरीक्षण के दौरान यह कार्रवाई की। ढाबों से मक्खन से सैंपल भरे गए। विभाग ने उक्त कारोबारियों को नोटिस जारी किए हैं। वनस्पति तेल और घी से तैयार किए जा रहे मक्खन पर प्रतिबंध है।

यह मक्खन तय मानकों के अनुरूप नहीं है। इस वजह से विभाग ने सैंपल भरे हैं। ढाबा संचालक लाभ कमाने के लिए बाजार से खरीदे के वनस्पति तेल और घी को देसी

विधि से मक्खन में ढाल रहे हैं और इस मारग्रेन पदार्थ को लोगों को परोसा जा रहा है। जिसका सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। संतोषजनक जवाब न आने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई की भनक लगते ही कई ढाबा मालिकों ने मक्खन को दुकानों से बाहर फेंक दिया। सैंपल लेने के बाद संयुक्त जांच प्रयोगशाला कंडाघाट भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट दो हफ्ते में आने की संभावना है। सैंपल फेल होने की सूरत में कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

लोगों को निम्न स्तर के तेल से बना मक्खन दिया जा रहा है। जिससे जहां लोगों को घटिया पदार्थ परोसे जा रहे हैं, वहीं अधिक कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। इससे पूर्व भी दिवाली को लेकर विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण के दौरान 27 मिठाइयों के सैंपल भरे थे। जिसका खुलासा भी रिपोर्ट आने के बाद होगा। उक्त कारोबारी लोगों को मक्खन की बजाए 10 रूपये में मारग्रेन बेचकर चूना लगा रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि कसौली स्थित ढाबों का निरीक्षण किया गया।

पानी के बिल और हाऊस टैक्स न चुकाने वालों को नगरपरिषद भेजेगी नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

नगर परिषद ने लंबे अरसे से पानी और हाउस टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके तहत नगर परिषद डिफाल्टरों को जल्द ही नोटिस भेजेगी। इसके लिए नगर परिषद ने डिफाल्टरों की सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे पूरा करने के बाद कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद के अनुसार शहर में हाउस टैक्स और पानी के बिलों का करोड़ों रुपये लोगों के पास फंसा है। पैसा फंसने से नगर परिषद में होने वाले विकास कार्यों पर रोक लगना शुरू हो चुकी है। अब ऐसे लोगों से पैसे का भुगतान करने के लिए नगर परिषद नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है।पानी के बिलों का भुगतान न करने वालों में साल में लाख कमाने वाले भवन मालिक, स्कूल और बड़े कारोबारी भी शामिल हैं जो पैसों का समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। हालांकि, अभी नगर परिषद ने सूची बनाने का कार्य तेजी से चला रखा है। इसके बाद डिफाल्टरों से पैसा वसूला जाएगा। नोटिस में लोगों को 15 दिन के भीतर पैसा चुकाने का समय दिया जाएगा। पैसा न

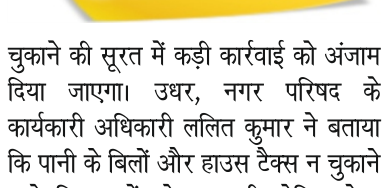

चुकाने की सूरत में कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उधर, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने बताया कि पानी के बिलों और हाउस टैक्स न चुकाने वाले डिफाल्टरों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सूची के अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मेडिकल कालेज नाहन में एमसीआई की दबिश, जांची व्यवस्थाएं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

अव्यवस्थाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाले डह. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में 5 नवंबर को एमसीआई की तीन सदस्यीय टीम ने दबिश दी। दिनभर टीम ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह साढ़े 9 बजे ही एमसीआई की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंच गई थी। षाम करीब 6 बजे तक टीम सदस्यों ने अलग - अलग ग्रुप बनाकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार व्यवस्थाओं की जांच की। हालांकि, टीम के कॉलेज पहुंचने का मुख्य मकसद एमबीबीएस के पांचवें बैच के लिए एलओपी (लेटर ऑफ परमिशन) जारी करने से पहले निरीक्षण करना था। महाराष्ट्र, असम और हरियाणा के रोहतक से पहुंचे टीम सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न हिस्सों का बारी-बारी से निरीक्षण किया। कॉलेज में अकादमिक गतिविधियों के साथ - साथ फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। निरीक्षण के बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

जब्त किए वाहनों से वसूला दो लाख टोकन टैक्स

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटी का खूब डंडा चला है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविंद्र शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने यातायात नियमों की अवहेलना पर पहले से जब्त तीन वाहनों से दो लाख रुपये टोकन टैक्स भी वसूला गया। कई वाहनों की जांच में खामियां पाए जाने की सूरत में जुर्माना वसूल किया गया। जब्त किए एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी और एक हाइड्रा वाहन से टोकन टैक्स वसूला गया है।

बिना दस्तावेजों और अन्य खामियों के पाए जाने वाले 185 वाहनों की जांच करने पर खामियां पाए जाने पर 75 वाहनों के चालान भी काटे और 12,800 रुपये का मौके पर जुर्माना वसूल किया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविंद्र शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने कार्रवाई के दौरान अनियमितताएं पाए जाने और दस्तावेजों की कमी समेत यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा। उनके चालान काटकर मौके पर ही जुर्माना वसूल किया है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जिले की सभी तहसीलों में अब बायोमीट्रिक से लगेगी हाजिरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

जिला हमीरपुर की सभी तहसीलों में अब बायोमीट्रिक मशीनें लगाने की तैयारी हो गई है। उपायुक्त ने हमीरपुर, बड़सर, भोरंज, सुजानपुर, टौणीदेवी, नादौन, गलोड़ समेत जिले के सभी तहसीलदारों को अपने-अपने तहसील कार्यालय में बायोमीट्रिक मशीनें लगाने के निर्देश दिए हैं।

अब राजस्व विभाग के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह पाएंगे। दूरदराज से राजस्व से संबंधित कामकाज के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए उपायुक्त ने यह निर्णय लिया है। वहीं, रजिस्टरों पर हाजिरी लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद होगी। रोजाना सुबह और शाम दिन में दो बार बायोमीट्रिक मशीन पर हाजिरी लगेगी। जिससे बिना बताए कार्यालय से गायब रहने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसने वाला है। लोगों को अपनी जमीन, आय, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेजों के लिए तहसील कार्यालय आना पड़ता है। लेकिन, आए दिन राजस्व विभाग के कार्यालयों में स्टाफ के अनुपस्थित रहने की शिकायतें मिलती हैं। जिससे कई किलोमीटर दूर से सफर तय करने के बाद तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को स्टाफ के मौके पर मौजूद न होने के चलते कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार-बार कार्यालय के चक्कर न काटने पड़ें और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने बायोमीट्रिक लगाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त हमीरपुर ने कुछ समय पहले बड़सर के एसडीएम और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया।

तहसील कार्यालय में कई कर्मचारी कार्यालय में नहीं मिले। हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो उसमें कर्मचारियों की हाजिरी नहीं पाई गई। इस पर उपायुक्त ने तहसीलदार को बिना बताए गायब रहने वाले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उधर, तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उपायुक्त हमीरपुर ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो रजिस्टर पर कई कर्मचारियों ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई थी। चूंकि कार्यालय की अधीक्षक के पास रजिस्टर होता है तथा वह उस दिन छुट्टी पर थीं। जबकि, कुछेक कर्मचारी भी अवकाश पर थे।

सहकारी सभा करलोटी में 12 करोड़ घोटाले की जांच मांगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, (बिलासपुर)

घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस की ओर से खाद्य एवं आपूर्ति व सहकारिता विभाग में कथित घोटालों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया गया। यह धरना पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी के नेतृत्व में दिया गया है। इस धरना में कांग्रेस के प्रबुद्ध लोगों ने मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घोटालों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया है।

घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में हो रहे घोटाले में खाद्य एवं आपूर्ति व सहकारिता विभाग में हो रही धांधलियों के बारे में कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। राशन घोटाले में घुमारवीं भाजपा के प्रवक्ता व जिला फैडरेशन के चेयरमैन का नाम आने पर कांग्रेस जांच की मांग कर रही हैं। कांग्रेस द्वारा क्षेत्र में सहकारी सभा करलोटी में हुए लगभग 12 करोड़ घोटाले की भी जांच की मांग की जा रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उक्त घोटाले में शामिल चहेतों को भाजपा द्वारा बचाया जा रहा है तथा जांच के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही हैं। कांग्रेस ने सरकार से निष्पक्ष एजेंसी से जांच की मांग की है तथा दोषियों के विरुद्ध शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष जागीर सिंह मेहता, कृष्ण लाल बरूर, सुनीता धीमान, निशा शर्मा, मेहर चंद, नंद लाल शर्मा, विनोद चंदेल, श्याम शर्मा, सतपाल, राजीव शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

नघ्यार पंचायत प्रधान और झबोला पंचायत उपप्रधान हुए निलंबित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा में 33 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में हिरासत में रहे 2 पंचायत प्रतिनिधियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। पंचायती राज अधिनियम के तहत 14 दिनों से अधिक समय के लिए हिरासत में रहे पंचायत पदाधिकारियों को पद से हटाने का प्रावधान है।

इसी के आधार पर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने नघ्यार पंचायत प्रधान सुशील कुमार और झबोला पंचायत उपप्रधान अश्विनी कुमार को पद से निलंबित कर दिया है। उन्हें पंचायत से संबंधित किसी भी तरह की संपत्ति या दस्तावेज सचिव को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा में करोड़ों रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। इसकी गाज सभा के कई सदस्यों पर गिर चुकी है।

पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इनमें नघ्यार पंचायत प्रधान सुशील कुमार और झबोला के उपप्रधान अश्विनी कुमार भी शामिल थे।

इन दोनों पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही सभा के अन्य सदस्य एक माह से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे हैं। अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। जानकारी के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के तहत 14 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर पंचायत प्रतिनिधियों को पद से हटाया जा सकता है।

नघ्यार पंचायत प्रधान व झबोला के उपप्रधान के एक माह से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने की वजह से उन्हें गत 22 अक्तूबर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने इसका जवाब भी दिया लेकिन वह तथ्यों के विपरीत और असंतोषजनक पाया गया।

ताजा घटनाक्रम में उपायुक्त ने पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नघ्यार के प्रधान सुशील कुमार व झबोला के उपप्रधान अश्विनी कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित कर दिया है। उन्हें यह भी आदेश दिया गया है कि यदि उनके पास पंचायत से संबंधित किसी भी तरह की चल-अचल संपत्ति है तो वे उसे पंचायत सचिव को सौंप दें।

सरकारी अधिकारी से आरडी के नाम पर लाखों की ठगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

जिले के एक सरकारी अधिकारी से फाइनेंस कंपनी ने लाखों का फ्राड किया है। आरडी के नाम पर व्यक्ति से लाखों की ठगी की गई है। आरडी मैच्योर होने के बाद जब संबंधित कंपनी से पैसा मांगा तो उसे दो लाख से अधिक का चेक दिया गया। जब उसने चेक क्लीयरेंस के लिए बैंक में लगाया तो यह बाउंस हो गया। पता चला कि जिस खाते से चेक दिया गया था उसमें पैसा ही नहीं है। इसके बाद व्यक्ति ने मामला पुलिस थाना बड़सर में दर्ज करवाया है।

व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने धारा 420 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधित व्यक्ति से आरडी करवाने से संबंधित सभी प्रमाण पुलिस ने मांगे हैं। पुख्ता सबूत एकत्रित करने के बाद पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। पुलिस थाना बड़सर के तहत अधिकारी ने यह मामला दर्ज करवाया है। शिकायत में उसने बताया कि उसने फाइनेंस कंपनी में पैसा जमा करवाया था। पैसा मैच्योर होकर दो लाख से अधिक हो गया था। एक लाख 20 हजार रुपये कंपनी में जमा करवाए थे। मैच्योरिटी के बाद भी उसे पैसा नहीं दिया गया। कंपनी ने दो लाख से अधिक का एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद व्यक्ति ने संबंधित फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। फाइनेंस कंपनी का कार्यालय मैहरे में बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। धारा 420 में मामला दर्ज किया गया है।

पंजगाई और धौन कोठी के 5 स्कूल 1.37 करोड़ से बनेंगे स्मार्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिले के पंजगाईं क्षेत्र के तहत पांच प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय 1.37 करोड़ की लागत से मॉडल स्कूल बनेंगे। इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव डाइट प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने जिला उपायुक्त और खनन विभाग के समक्ष रखा था। विभाग की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग मंजूरी मिल चुकी है। थोड़ी औपचारिकताओं के बाद विभाग उक्त राशि को जारी कर देगा ताकि स्कूलों में बच्चों को अच्छे स्तर पर सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस प्रोजेक्ट से जहां सरकारी स्कूलों की हालत सुधरेगी वहीं इन स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी।

उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों के भवन निर्माण, बच्चों के बैठने की सुविधा, पीने के पानी, स्कूल गतिविधियों के लिए खेल के मैदान और कई प्रकार की ऐसी खामियां हैं जिनके कारण अभिभावक सरकारी शिक्षा संस्थानों की जगह निजी शिक्षण संस्थानों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। इसके लिए वो इन निजी शिक्षण संस्थानों को भारी भरकम रकम हर माह अदा करते हैं।

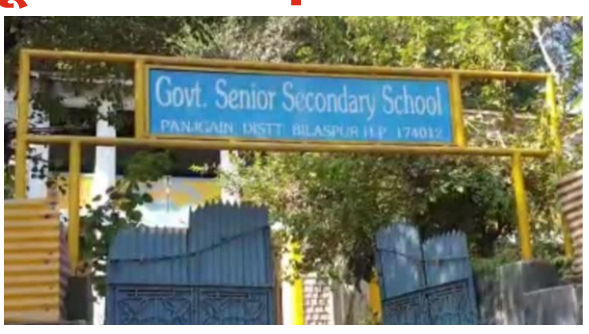

डाइट प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल और खनन विभाग के समक्ष दिल्ली की तर्ज पर जिला के पांच स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा था।

खनन विभाग के तहत आने वाले ग्राम पंचायत पंजगाईं के स्कूलों को मॉडल स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा जिसमें प्राथमिक स्कूल थड़मनाल, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल धौन कोठी, प्राथमिक पाठशाला कुनणु, प्राथमिक पाठशाला बाग, और रावमापा पंजगाईं शामिल हैं। डाइट प्रधानाचार्य राकेश पाठक का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम, स्वच्छ पेयजल के लिए एक्वागार्ड, आर्ट एंड क्राफ्ट, बाल गतिविधि, रिटेनिंग वाल, बाउंडरी वाल और गेट, अग्नि नियंत्रक यंत्र, कंप्यूटर फर्नीचर, स्टूडेंट फर्नीचर सहित वो हर चीज लगाई जाएगी जो मॉडल स्कूल के लिए आवश्यक होगी। कहा कि अगर जिले का हर स्कूल मॉडल बनेगा तो कोई भी बच्चा निजी संस्थानों में पढ़ने नहीं जाएगा। वहीं बच्चों को मिलने वाली शिक्षा में भी गुणवत्ता आएगी।

बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग तैयार

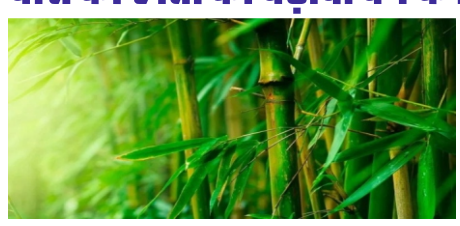

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

प्रदेश में कम होती बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। कृषि विभाग किसानों को बांस के पौधे मुफ्त में देगा। विभाग इस पर 20.34 करोड़ खर्च करेगा। विभाग बांस की नर्सरी से लेकर स्वरोजगार के लिए भी मदद करेगा। उन कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा, जो बांस के पौधों से किलटे, टोकरियां और अन्य साजो समान बनाते हैं। बांस की पत्तियों का पशुओं के चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पत्तियों से खाद तैयार की जाएगी। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है। उन्हें खाली जमीन मुहैया करवाई जाएगी। बांस के पौधों को उगाने और रखरखाव का जिम्मा किसानों के समूह का होगा। किसानों को इसे काटने के लिए भी वन विभाग की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। ब्लॉक के हर गांव में बनाया जाएगा किसानों का समूह बांस की खेती करने के लिए विभाग की ओर से ब्लॉक के हर गांव के करीब 25 से 30 किसानों का समूह बनाया जाएगा। इसके साथ विभाग की ओर से किसानों को जल्दी बढ़ने वाले बांस के पौधे दिए जाएंगे। बांस की नर्सरी लगाने से व्यवसाय चलाने तक कृषि विभाग किसानों को सहायता देगा। योजना में किसानों को बांस खेती और बांस का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। किसानों को नर्सरी और बांस की वस्तुओं को बनाना भी सिखाया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी मोहेंद्र सिंह भवानी ने कहा कि विभाग जल्द ही ब्लॉकों का दौरा करेगा। जमीन का चयन कर किसानों का समूह बनाया जाएगा।

पेयजल योजना के पंपों पर ठेके पर रखे कर्मियों की मंत्री ने मांगी रिपोर्ट

द रीव टाइम्स, हमीरपुर

विधानसभा क्षेत्र नादौन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरा में हाल ही में आईपीएच एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र की दस पंचायतों से कुल 54 समस्याएं प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश का मौके पर निपटारा किया गया। जनमंच में मानखड्ड का चौनलाइजेशन, पेयजल योजना के पंपों को ठेके पर देने, सीवरेज, सड़कों की खस्ता हालत आदि मुख्य समस्याएं आईं। मंत्री महेंद्र ठाकुर ने जनमंच में प्रदत्त सेवाओं का अवलोकन किया और एक बूटा बेटी के नाम योजना के अंतर्गत पाठशाला परिसर में चिनार का एक पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने जनमंच में अनुपस्थित पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए। कहा कि जनमंच में हर अधिकारी का पहुंचना आवश्यक है परंतु यदि कोई सूचना के बावजूद भी न पहुंचे तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेयजल योजना के पंपों को ठेके पर देने और ठेकेदारों की ओर से रखे ऑपरेटरों की समस्या सुनने के बाद मंत्री ने आदेश दिए कि इस तरह की ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाएगा तथा इस संबंध में आगामी योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने जिलाभर के ऐसे पंपों पर ठेकेदारों के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों की भी रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने जनमंच में आई शिकायतें प्रस्तुत कीं। उन्होंने आश्वस्त किया कि निपटारे के लिए शेष शिकायतों का समयबद्ध समाधान कर दिया जाएगा। उपमंडलाधिकारी नादौन किरन भड़ाना ने पूर्व जनमंच चरण में आयोजित गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।

प्लास्टिक से पेट्रोल – बिजली होगी उत्पन्न

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में तीन दिवसीय जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बलवंत नड्डा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्वनी चंबियाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में 90 स्कूलों के 415 बच्चे भिन्न-2 प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान काल विज्ञान का है और हमारे सामने विभिन्न चुनौतियां हैं। जिनमें कूड़ा कर्कट का निष्पादन, बिजली उत्पादन, प्रदूषण तथा जल संकट मुख्य रूप से है। बाल विज्ञान सम्मेलन का इस वर्ष का थीम स्वच्छ भारत और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान तकनीक और नवाचार रही। जिसके तहत बच्चों ने विभिन्न प्रोजेक्ट बनाए हैं। सम्मेलन में 80 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 40 मॉडल पेश किए जा रहे हैं। इस बाल विज्ञान सम्मेलन में रावमापा जंदड़ू के छात्र विशाल कुमार द्वारा प्लास्टिक निपटान को पेश किया।

प्लास्टिक मुक्ति धाम नामक मॉडल और हिम अकादमी हीरानगर की छात्राओं द्वारा प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबेल मैटीयिरल से पेट्रोल और बिजली बनाने वाले मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अब डीएनए का रहस्य समझना होगा आसान आईआईटी मंडी ने तैयार किए मॉडल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

अब मनुष्य समेत किसी भी जीव या वस्तु के डीएनए एवं संरचना के रहस्य को समझना आसान होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के शोधकर्ताओं ने डीएनए से जुड़ी पॉलीमर लूपिंग की प्रक्रिया समझने के लिए आसान मॉडल विकसित किए हैं। साथ ही पॉलीमरिक लूप सिस्टम एंड लूप मैकेनिज्म के मौलिक पहलुओं को समझने के लिए सैद्धांतिक मॉडल बनाए हैं। आईआईटी मंडी में स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अनिरुद्ध चक्रवर्ती की देखरेख में यह शोध किया गया है। अंतरराष्ट्रीय जर्नल केमिकल फिजिक्स लेटर्स में उनका अध्ययन हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उनकी शिष्या मोमीता गांगुली इस शोध पत्र की संबद्ध लेखिका हैं।

शोधकर्ताओं का दावा है कि नई प्रक्रिया से न केवल जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में लूपिंग के महत्व को समझने का बल्कि नैनो-डिवाइस और पॉलीमर से मोलेक्युलर मशीन विकसित करने में भी मदद मिलेगी।

रसायनिक प्रतिक्रियाएं बड़ी तीव्रता से घटित होती हैं। लूपिंग की इन प्रतिक्रियाओं की गति को समझने के लिए गणित के एक अति सरल एक पक्षीय मॉडल तैयार किया है ताकि पॉलीमर की लंबाई, रिलेक्सेशन समय और बांड की लंबाई जैसे सरल मापदंडों के आधार पर इसमें शामिल काइनेटिक्स का कोई सिद्धांत सामने आ सके। विशेष कर लंबे पॉलीमर के सिरों के बीच संपर्क की अधिकता पाई जाती है और ये जैविक पॉलीमर के लिए जरूरी हैं।

हमारे जेनेटिक पॉलीमर डीएनए की लूपिंग के लिए हमारे ब्लू प्रिंट और एमीनो एसीड (जिनसे प्रोटीन बनता है) के वाहक का काम करने के लिए जरूरी है। पॉलीमर का एक क्रम में लूप बनना अनिवार्य है ताकि वे अपने होने का उद्देश्य पूरे करें।

भीषण अग्निकांड ने 11 परिवारों से छिना रोजी–रोटी का सहारा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, (चंबा)

सलूणी मुख्य बाजार में हाल ही मे हुए अग्निकांड ने कई परिवारों के सामने रोजी रोटी छीन ली है। आग की लपटों में जहां उनकी दुकानें जल गई तो उसमें रखा करोड़ों का सामान भी जल गया। ऐसे में अब दुकानदारों के सामने संकट इस बात का खड़ा हो गया है कि वह घाटे की भरपाई करेंगे या फिर परिवार चलाने के लिए कारोबार दोबारा शुरू करें। भीषण अग्निकांड में कमाई का जरिया खोने का गम में सभी की आंखों नम हो गई। भीषण अग्निकांड ने नंदला निवासी 37 वर्षीय हेमराज पुत्र सत्य प्रसाद को कभी न भूलने वाले जख्म दिए हैं। हेमराज अपने परिवार, बूढ़ी मां के पालन-पोषण के लिए सलूणी बाजार में किराये की दुकान लेकर कपड़े सिलाई का काम करता है। हेमराज रोजाना तीन किलोमीटर का पैदल सफर तय कर दुकान पर पहुंचकर काम में जुट जाता था। बकौल हेमराज के मुताबिक उनके घर में उनकी पत्नी दर्शना देवी, बूढ़ी मां चेलों देवी, दो बेटे (12 वर्षीय बेटा देवेंद्र और 9 वर्षीय बेटा मनीष) हैं। बूढ़ी मां की दवाईयों का खर्च, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और परिवार का खर्च उनका इसी दुकान से चलता था। हेमराज के जहन में अब सिलाई के लिए कपड़े छोड़ गए लोगों को कपड़े या पैसे वापिस करने को लेकर कड़ी कशमकश चली हुई है। बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखने वाले हेमराज की इस अग्निकांड ने मानों रीढ़ ही तोड़ कर रख दी है। बाजार में किराये पर दुकानें लेकर काम करने वाले अन्य दुकानदारों में सब्जियों के बीज बेचने वाले धर्मचंद, टी स्टाल चलाने वाले सुरेंद्र कुमार, इलेक्ट्रिशन का काम करने वाले सुदेश कुमार, स्टोर मालिक तिलकराज, बच्चों के खिलौने के दुकानदार टेक चंद, मेडिकल स्टोर विक्रेता नजाकत अली, कपड़े सिलाई करने वाले वीरेंद्र कुमार, सोनू और जोगेंद्र शामिल है।

आदर्श स्कूल में शिक्षक नहीं, छात्रावास बदहाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहलमा में शिक्षकों की कमी है। इतना ही नहीं पाठशाला में लड़कियों के लिए बने छात्रावास की हालात दयनीय बनी है। आलम यह है कि स्कूल की 12 छात्राओं के इस हॉस्टल में आज दो ही छात्राएं हैं।

छात्रावास की दयनीय हालात को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं रखना चाहते हैं। छात्रावास में रसोईया तक नहीं है। पाठशाला की एक शिक्षिका ही अपने स्तर पर छात्रावास की देखरेख कर रही है। कमरों की भी हालत काफी खराब है। कई कमरों की छत से बारिश के साथ बर्फ का पानी भी टपकने लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहलमा को आलीशान भवन दिया है। लेकिन पाठशाला में अध्यापकों की तैनाती नहीं कर रही है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थी पढ़ाई को मजबूरी में जिले से बाहर का रुख करना पड़ रहा है। पाठशाला में अध्यापकों के तैनात होने से छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। उपमंडल उदयपुर के अंतर्गत जाहलमा पंचायत की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाहलमा में स्टाफ की कमी है। इस पाठशाला में नवंबर 2016 से फिजिक्स, 2018 से इतिहास प्रवक्ता के साथ ही जनवरी 2019 से टीजीटी नॉन मेडिकल का पद खाली चल रहा है।

इसके अलावा कार्यालय में जुलाई 2019 से वरिष्ठ सहायक तथा अगस्त 1995 से सहायक लाइब्रेरियन का पद भी खाली चल रहा है। 31 अक्तूबर को इस पाठशाला में तैनात प्रधानाचार्य का भी यहां से तबादला हो गया है।

बता दें कि इस पाठशाला में जाहलमा, नालडा, मूरिंग, गोहरमा और जोवरंग पंचायतों के दो दर्जन से अधिक गांव के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों ने विधायक और विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस पाठशाला में शिक्षकों के खाली पदों को भरा जाए।

प्रारूपकार संघ के अध्यक्ष बने रमेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

प्रारूपकार संघ का अध्यक्ष रमेश यादव को चुना गया है। रविवार को एनजीओ भवन मंडी में प्रारूपकार संघ (पीडब्ल्यूडी और आईपीएच) की जिला कार्यकारिणी के चुनाव प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुए। इसमें प्रताप सिंह को वरिष्ठ उपप्रधान, चेत राम को महासचिव, जय सुखलाल और शांता देवी को उपप्रधान, प्रवीण कुमार को कोषाध्यक्ष, हंस राज को मुख्य सलाहकार तथा पंकज, तिलक शर्मा, जगदीश कुमार, मेघ सिंह, बृज लाल, पुनीत शर्मा, रोशन लाल, सुरेश कुमार, प्रवीण कुमार, भगत राम, दिनेश कुमार, तुलसी राम, हुक्म चंद और घनश्याम सिंह को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। अध्यक्ष ने कहा कि पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग के प्रारूपकारों की जो भी मांगें और समस्याएं होंगी, उन्हें सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को राज्य कार्यकारिणी के गठन के बाद मांगपत्र तैयार किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने आए प्रदेशाध्यक्ष अमर सिंह ठाकुर ने जिले की नई कार्यकारिणी को बधाई दी। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को ऊना में राज्य कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने सभी जिलों के सदस्यों से भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नई कार्यकारिणी को सभी के सहयोग से चुना जाएगा।

स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, स्कूल में शिक्षक नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जनजातीय क्षेत्र लाहौल की थिरोट पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पांच माह से चिकित्सक का पद खाली चल रहा है। एक साल से अधिक समय से यहां के पशु औषधालय में फार्मासिस्ट का पद भी नहीं भरा गया है। पीएचसी थिरोट में डॉक्टर और पशु औषधालय में फार्मासिस्ट डेपुटेशन पर भेजे जा रहे हैं। बर्फबारी के दिनों यह दिक्कत और बढ़ जाएगी। स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार स्थानीय विधायक को अवगत करवाया है। लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लाहौल घाटी के उपमंडल उदयपुर के अंतर्गत थिरोट पंचायत के लोगों ने मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की है। साथ ही थिरोट पाठशाला में प्रधानाचार्य के साथ साइंस अध्यापक की तैनाती की मांग भी उठाई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है थिरोट पीएचसी में फार्मासिस्ट ही तैनात है। लेकिन पशु औषधालय में फार्मासिस्ट का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। स्थानीय निवासी राजेश कुमार ने कहा कि पीएचसी में अस्थायी डॉक्टर व पशु औषधालय में अस्थायी फार्मासिस्ट समाधान नहीं है। सर्दियों के दिनों में बर्फबारी के बीच कोई भी डॉक्टर व फार्मासिस्ट थिरोट में अस्थायी सेवाओं के लिए नहीं पहुंच पाएंगे।

थिरोट पीएचसी, पशु औषधालय से थिरोट के साथ सिंदवाड़ी और झोलिंग गांव के लोग भी लाभान्वित होते हैं।

डॉक्टर, शिक्षक नहीं

सिंदवाड़ी गांव की प्रेमी देवी का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा का ढांचा सुदृढ़ होना चाहिए। कहा कि पीएचसी में डॉक्टर और स्कूल में अध्यापक न होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थायी स्टाफ की तैनाती हो

लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में अस्थायी व्यवस्था से काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल में स्थायी स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए। सरकार व विधायक को प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने की पहल करनी चाहिए।

राजन का कहना है कि सुविधाओं को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेता किसी भी पार्टी का हो उसे भेदभाव के बिना ही विकास करना चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार और प्रशासन गंभीरता दिखाए।

होटल व ढाबा संचालकों को लाइसेंस लेना जरुरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के सौजन्य से बंजार के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह खुंदन में फोसटेक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यशाला लगाई गई।

कार्यशाला में होटल संचालकों, रिसॉर्ट, कैंप साइट, रेस्तरां और ढाबा चालकों ने हिस्सा लिया। खाद्य पदार्थ विक्रेताओं व कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा भावीता टंडन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 31 (1) के तहत भारत के हर खाद्य व्यापार संचालक को इसके लिए लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े सभी होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे, लॉज, कैंप साइट, रेस्तरां और ढाबा संचालकों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए सफाई का ध्यान रखें। इस दौरान भगवान सिंह राणा, ललित कुमार, वरूण भारती, संदीप कंवर, इंदु पटियाल, मोहर सिंह राठौर, शारदा कटोच, जसविंद्र सिंह, अंकित, झाबे राम, यज्ञ चंद, मोहन ठाकुर, ईशान, खेम भारती, बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे।

99 में से 72 मांगों और समस्याओं का मौके पर निपटारा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

विधानसभा क्षेत्र भटियात के तहत नगर पंचायत चुवाड़ी के आंबेडकर भवन त्रिमथ में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। इस कार्यक्रम से ग्राम पंचायत काहरी, अवां, गाहर, जतरुन, परछोड़, कुडणु व नगर पंचायत चुवाड़ी के लोग लाभान्वित हुए। इस अवसर पर शिकायतों व मांगों से संबंधित 99 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से 72 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया तथा अन्य को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

मंत्री ने अधिकारियों को जनमंच में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनमंच से पहले, पूर्व जनमंच गतिविधियों के माध्यम से भी लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत 20 लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए। साथ ही बेटी है अनमोल योजना के तहत 13 लाभार्थियों को एफडी भी प्रदान की गई।

जिले की स्वच्छ पंचायतों को सम्मानित करेगा प्रशासन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

मंडी जिले में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन जिले की संपूर्ण स्वच्छ पंचायतों को सम्मानित करेगा। ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर सबसे बेहतर काम करने वाली 3 पंचायतों को जिला स्तर और हर ब्लॉक से एक पंचायत को ब्लॉक स्तर का पुरस्कार दिया जाएगा। अवार्ड के लिए पंचायतों को खुद अपना दावा बीडीओ के पास पेश करना होगा। प्रधान व सचिव बीडीओ कार्यालय में अवार्ड के लिए अपनी पंचायत का नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन के बाद पंचायतों में ठोस व कचरा प्रबंधन के लिए किए गए काम के साथ साथ स्वच्छता के अन्य मानकों के अनुरूप काम को देख परख कर बीडीओ मामला जिला प्रशासन को भेजेंगे। जिस पर अंतिम निर्णय जिला स्तर पर लिया जाएगा। 26 जनवरी को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ऋग्वेद ठाकुर ने सभी बीडीओ को अपने अपने क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों को इन अवार्ड के बारे में जागरूक करने को कहा।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग, परियोजना अधिकारी डीआरडीए नवीन शर्मा, जिला योजना अधिकारी जवाहर लाल, जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह, सभी बीडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्र में पंचायतों में पॉलिथीन एकत्रण केंद्र स्थापित करवाने को कहा। निर्देश दिए कि सभी बीडीओ तय करें कि उनके ब्लॉक में सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा कर नगर परिषद मंडी को दिया जाए। नगर परिषद इसे 75 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पॉलिथीन एकत्रण के लिए पंचायतों में लोगों को प्रोत्साहित करें।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

आजीवन कारावास की सजा कितने साल की होती है? कानून की नज़र से जानें

आजीवन कारावास यानि उम्रकैद की सजा गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 में अपराधों के दंड के विषय में विस्तार से बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं। भारतीय दंड संहिता कुल पांच तरह के दंड का प्रावधान करती है ।

- मृत्यु दंड
- आजीवन कारावास
- कारावास : यह कारावास दो प्रकार का है, पहला सश्रम कारावास और दूसरा सादा कारावास (किसी श्रम के बिना)
- संपत्ति का समपहरण
- जुर्माना आजीवन कारावास की अवधि : यह देखा गया है कि आजीवन कारावास की अवधि के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं जैसे कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है या 20 साल का? लेकिन यह सब गलतफहमी है, क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ है कि सजा पाने वाला व्यक्ति अपने बचे हुए जीवनकाल तक जेल में रहेगा। जब कोई अदालत किसी अपराध के लिए किसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है तो विधि के समक्ष इस सजा की अवधि का अर्थ सजा पाने वाले व्यक्ति की अंतिम सांस तक होता है। अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा । यही आजीवन कारावास का अर्थ है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में की है।

सरकार को सजा कम करने का अधिकार

कई बार यह देखने में आया है कि आजीवन कारावास पाए गए व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया जाता है। हालांकि उसे आजीवन कारावास के रूप में अपना पूरा जीवन कारावास में बिताने की सजा मिली थी, लेकिन समुचित सरकार निश्चित मापदंडों पर किसी व्यक्ति की सजा कम करने की शक्ति रखती है । यही कारण है कि हम सुनते हैं कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा व्यक्ति 14 साल या 20 साल बाद रिहा हुआ । भारतीय दंड संहिता की धारा 55 और 57 में सरकारों को दंडादेश में कमी करने का अधिकार दिया गया है । इस अधिनियम की धारा 55 कहती है, ''हर मामले में, जिसमें आजीवन का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए, जो चौदह वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी।' यहां समुचित सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसके अंतर्गत मामला आता है । जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार । इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 57 किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना के संबंध में है। धारा 57 कहती है, दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसका अर्थ है कि जब कभी किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना करने की आवश्यकता होगी तो उसे 20 वर्ष के समान माना जाएगा । इसका यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है, बल्कि यदि कोई गणना करनी हो तो आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाएगा। गणना करने की आवश्यकता उस स्थिति में होती है जबकि किसी को दोहरी सजा हुई हो या किसी को जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त समय के लिए कारावास में रखा जाता है।

सरकार कर सकती है सजा में कमी, यह है प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Crpc) की धारा 433 में समुचित सरकार द्वारा दंडादेश के लघुकरण का प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Crpc) की धारा 433 कहती है, ''दंडादेश के लघुकरण की शक्ति कृसमुचित सरकार दंडादिष्ट व्यक्ति की सम्मित के बिना

(क) मृत्युदंडादेश का भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबिन्धत किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है।

(ख) आजीवन कारावास के दंडादेश का, चौदह वर्ष से अनिधक अविध के कारावास में या जुमाने के रूप में लघुकरण कर सकती है।

(ग) कठिन कारावास के दंडादेश का किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में जिसके लिए वह व्यक्ति दंडादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।

(घ) सादा कारावास के दंडादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है। उक्त प्रावधान के तहत सरकार को सजा का लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। अच्छे आचरण के आधार पर आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कई ऐसे लोगों को कई साल की सजा के बाद सरकार उनकी सजा का लघुकरण करते हुए उन्हें रिहा करती है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

आपका स्वास्थ्य हमारा परामर्श

हमारी किडनी और बीमारी के लक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

किडनी हमारे शरीर में सफाई का काम करती हैं। यह गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। दोनों किडनियों में खून साफ होता है। हमारी दोनों किडनियों में छोटे-छोटे लाखों फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफरोंस कहते हैं। नेरोफेंस हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। किडनी में होने वाले इस सफाई सिस्टम के कारण हमारे शरीर से हानिकारक तत्व पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं। किडनी के अन्य कामों में लाल रक्त कण का बनना और फायदेमंद हार्मोंस रिलीज करना शामिल हैं। किडनियों द्वारा रिलीज किए गए हार्मोंस द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी विटामिन डी का निर्माण किया जाता है।

जानिए कुछ ऐसे लक्षण जो किडनी संबंधी बीमारियों की दस्तक हो सकते हैं–

1 युरिनरी फंक्शन में बदलाव : सबसे पहला लक्षण जो उभर कर आता है वह है युरिनरी फंक्शन में बदलाव। किडनी में किसी प्रकार की समस्या के चलते पेशाब के रंग, मात्रा और कितने बार पेशाब आती है, इन चीजों में बदलाव आ जाएगा। इसके अलावा आप इन लक्षणों पर ध्यान दे सकते हैं

- रात में बार बार पेशाब आना।
- पेशाब की इच्छा होना परंतु बाथरूम में जाने पर पेशाब न होना।
- हमेशा से ज्यादा गहरे रंग में पेशाब आना।
- झाग वाली और बुलबुलों वाली पेशाब आना।
- पेशाब में खून दिखना।
- पेशाब करने में दर्द होना या जलन होना।

अच्छे स्वास्थ्य में शरीर के सभी अंगों का सुचारू संचालन बेहद जरूरी है। किडनी हमारे शरीर में दिन रात काम करती हैं और हमें स्वस्थ रखती हैं। दिए गए किसी भी लक्षण को अनदेखा न करें। ये आगे विकराल रूप में आने वाली समस्या की दस्तक हो सकते हैं। जैसी आप कुछ भी अलग महसूस करें अपने डॉक्टर से संपर्क कर सही कारण का पता लगाए। इस प्रकार समस्या छोटे रूप में ही सुलझाई जा सकती है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

शेष भाग अगले अंक में

सही कैरियर का चुनाव कैसे करें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हर इंसान को अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए अपने करियर का सही चुनाव करना पड़ता है इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है की वह अपने करियर का सही तरह से चुनाव करे इसीलिए अगर आपको भी अपने करियर का चुनाव करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हम आपको बताते है की आपको अपने सही करियर का चुनाव किस प्रकार से करना पड़ेगा ? करियर का का चुनाव करते समय हमारे सामने बहुत समस्या आती है हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लेकिन उन सब कन्फ्यूजन को दूर करके भी आप अपने करियर का सही चुनाव कर सकते है ।

अपने करियर की प्लानिंग करे

अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करियर की का चुनाव सही तरीके से करें तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है अपने करियर की प्लानिंग की इसीलिए करियर की प्लानिंग करने के लिए आपको यह सोचना पड़ता है कि आपको अपने करियर की योजना किस प्रकार करनी है इसीलिए अपने करियर का सही चुनाव करने के लिए अपने प्लानिंग करें उसके बाद कि आप अपने करियर का सही चुनाव कर पाएंगे ।

दूसरे लोगों से सलाह ले सकते है

ज्यादातर लोग जब कनफ्यूजन में होते हैं तो अन्य लोगों की सलाह लेते हैं इसीलिए आप भी अपने करियर का सही चुनाव करने के लिए अपनों से बड़े या फिर एक्सपीरियंस लोग हैं उन से सलाह ले सकते हैं वह आपको आपके करियर के बारे में सही जानकारी दे सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में अपना करियर है

अपने इंटरेस्ट को जाने आपको किस करियर में इंटरेस्ट है

हर व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है इसीलिए अगर आप अपने करियर का सही तरह से चुनाव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ? जब आपको अपनी रुचि के बारे में पता लग जाता है तो उसके बाद आप अपने करियर पर फोकस कर सकते हैं आप उसी लाइन में अपना कैरियर बनाने के लिए उत्साह तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं ।

अपनी प्रतिभा को पहचाने की आपकी क्या प्रतिभा है ?

जिस तरह से हर इंसान का इंटरेस्ट किसी ना किसी चीज में होता है उसी तरह हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट या प्रतिभा छुपी रहती है । इसीलिए आपको अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना होगा और आपकी जो प्रतिभा है उसी के अनुसार उसी क्षेत्र में अपने आप को निखार के उसी करियर का चुनाव करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने उस कार्य या करियर में सफलता हासिल कर सकते हैं ।

करियर के मार्गदर्शन के कुछ टिप्स

आप जो करना चाहते है उसके लिए उत्साहित रहे । अगर आपके अंदर उत्साह होता है तो आप के लिए हर काम आसान हो जाता है और आप उस काम को जल्द से जल्द सफलतापूर्वक करने की कोशिश करते हैं । इसीलिए हर इंसान के अंदर उत्साह की भावना होना जरूरी है इसलिए आप अगर सोच लेते हैं कि आपको किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आप को उत्साहित होना पड़ेगा तभी आप उस क्षेत्र में अपना करियर बना पाएंगे व सफलता हासिल कर पाएंगे ।

आत्मविश्वास बनाये रखे

ज्यादातर इंसान अपने करियर का सही चुनाव केवल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है । जैसे कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहे तो वह यही सोचता है कि विज्ञान विषय मेरे लिए बहुत कठिन पड़ेगा इसीलिए वह इंजीनियर नहीं बनता है और उस लाइन को नहीं चुनता । लेकिन आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है और जिस कार्य के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसी का चुनाव पुरे आत्मविश्वास के साथ करना है ।

आखिर हम गहरी निद्रा से कब जागेंगे

श्रीमद्भगवद् गीता में श्री कृष्ण के गायन को लगभग 5000 वर्ष का माना जाता है। जिसमें उन्होंने विशुद्ध ज्ञान की बात की तथा सभी प्रकार की धार्मिक भ्रांतियों का खंडन करते हुए यथोचित् मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन समाज की भ्रांतियां बनी रही। बहुत से ऋषिगण आए और गौतोक्त मार्ग को अपना आधार बनाते हुए आगे बढ़ते गए। इसी कड़ी में महावीर जैन तथा गौतम बुद्ध अवतरित हुए और 'अहिंसा ही परमो धर्मः' का ज्ञान देकर चले गए। लेकिन सामाजिक बुराईयों ने अपनी जड़ मजबूत बनाए रखी। कुछ समय पूर्व अवतरित हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद योगानंद आई कई विभूतियों ने इस धरा पर आकर मानवता को जगाने के प्रयास किए। लेकिन इन सभी के प्रयासों का फल मात्र कुछ ही व्यक्तियों को मिल सका। सामाजिक विकृतियां फिर भी बनी रही जबकि उनका आकार, आयतन व पुनरावृति की संख्या काफी कम हुई हैं। एक ओर हम चांद पर बसेरा बनाने की बात कर रहे हैं तथा दूसरी ओर हम चांद के प्रकोप से बचने के लिए चांद की पूजा करते हैं। स्थिति यहां तक है कि हिमाचल में जहां 60 वर्षों तक की उम्र में 100 प्रतिशत साक्षरता दर है वहां भी एक ऐसा ही एक कुकृत्य हमारी बीमार मानसिकता से ग्रसित सामने आया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र का विषय होने से मीडिया में जगह मिली। एक वृद्ध महिला को 'डायन' की संज्ञा देकर दिन दिहाड़े जूतों की माला पहनाकर समूचे क्षेत्र को शर्मसार कर दिया गया। अभी प्राथमिकी दर्ज कर मामला ठंडा भी नहीं हुआ, तो ऐसा ही दूसरा मामला प्रकाशित हुआ। एक महिला पुजारिन ने देवता की ओर से एक अन्य महिला को भीड़ से पिटवाया और उस पर थूकने का फरमान सुनाया। इतना ही नहीं सेवानिवृत शिक्षक भी इस प्रकार की यातना से अछूते नहीं रहे। पुलिस के सामने पीटने की शिकायतें भी मिली। ऐसे में कौन रोए-कौन सुने- किसको सुनाएं ? सरकार ऐसे विषयों को जांच और कचहरी तक सीमित रखती है जबकि इसी जड़ में जाने से परहेज करती है।

जब तक सरकार समर्थित प्रसार -शिक्षा पर कार्य नहीं होता, ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। समय की मांग सुनियोजित सामाजिक चेतना व जागृति लाने बारे कार्य करने की है।

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

Mission RIEV and Sustainable Development Goals

Being apex international body, the United Nations keeps on setting agenda for human development periodically. After the Millennium Developmental Goals (MDGs), the introduction of Sustainable Development Goals (SDGs) outlines promotion of 17 aspects of overall well-being of the living being on earth and every country makes efforts to work for achievements of these goals through various means and measures.

On the other hand, Mission RIEV is also mandated to create ease of living and progress in life through facilitation support services. Wherever, people find difficulty in any of the aspects impacting life style or progress, whether individual or collective, the role of Mission RIEV starts. The activities, services and the support system envisaged under Mission RIEV are touching all 17 goals defined by United Nations as Sustainable Development Goals as outlined below:

1. Formation of Advisory Bodies- The Bodies being formed at Gram Panchayat, Block, District and State level have the mandate not only to provide guardianship and mentorship support to the Mission at appropriate level, but to plan, and execute activities pertaining to the common good close coordination with the communities. These activities include Emergency Services Disaster Risk Reduction (DRR), afforestation in denuded forest patches, water conservation and water usage, sanitation including overall cleanliness, maintaining water bodies, promotion of pesticide free natural farming, strengthening local governance institutions for promoting transparency and accountability, etc. These activities have direct relationship with the SDG NO.6 (Clean Water and Sanitation), SDG No. 13 (Climate Action), SDG No.14 (Life Below Water), SDG No.15 (Life on Land) and SDG No. 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).

2. Institutionalized Service Division: Ten Service Divisions have been institutionalized under Mission RIEV to provide various felt need services and these Service Divisions have been trying to establish partnerships with the agencies owing the service products for operationalizing under Mission RIEV.

The multiple partnership initiatives with LIC India and SBI General Insurance Corporate agency, Bank of Baroda for getting 3500 POS machines etc., are adding values to the activities and service delivery of Mission RIEV and part of the SDG No. 17 (Partnership For the Goals). The Division Specific are briefed as below:

2.1. Education, Training & Counselling: As per the need assessment of the family especially in villages, the e-learning method of the Learning Management System is gaining wide popularity. Counselling and skill training are also being covered under this Division. The quality education is being provided even in the remote areas where teachers hardly serve with interest. These services significantly touch the SDG No. 4 (Quality Education).

2.2 Comprehensive Healthcare: Health Services are being provided at the door steps of the people right from medical test, video-conferencing with medical experts, supply of generic medicines at their door steps and follow up as well as referral appointment support. Apart from this, the preventive health education is also very important part of the Division Services. These services have direct relationship with SDG No. 3 (Good Health & Well Being).

2.3 Agri-Horti-Live Stock Services:

The services under this Division are primarily to promote and support natural practices and gradually zero downing the use of pesticides and other hazardous chemicals in agriculture, horticulture and livestock practice. The reduced pesticides and hazardous chemicals will prevent the aqua lives from depletion besides encouraging safe food production. These services have relationship with the SDG No. 1 (No Poverty), SDG No. 2 (Zero Hunger), SDG No.12 (Responsible Consumption and Production), SDG No.14 (Life Below Water).

2.4 Entrepreneurship and Business Development:

The services under this Division constitute identification of business potential in the aspirants, resource analysis, training needs assessment, orientation and training, bank linkages and providing business setup support besides mentorship for minimize one-year period for any start up. These services are directly related to the SDG No. 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG No. 9 (Industry Innovation & infrastructure) and SDG No. 5 (Gender Quality) women being encouraged under the services.

2.5 Banking and Financial Services:

The services under this Division include making due diligence, preparing loan cases including development of business proposals with financial analysis and getting the loans sanctioned followed by scheduled recoveries as well. These services have relationship with SDG No. 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) and SDG No.10 (Reduced Inequality) as the services are being provided to those weaker section people who keep on suffering because of the lengthy banking procedures and lose interest in furtherance of their objectives.

2.6 Land and Property Management:

There have been a number of land and property related pending concerns of the people in villages. The revenue authorities are not easily assessable and the procedures are also cumbersome with typical terminology beyond common person's understanding. Providing facilitation support services for fast and accurate resolution is mandate under the services of this Division and can have relationship with the SDG No.10 (Reduced Inequalities) and SDG No.16 (Peace Justice and Strong Institutions).

2.7. Rural Produce Marketing:

Under this Division, the farmers are facilitated with the quality production and getting reasonable and premium prices from the market as the farmer have to dispose-off their produce for loss many a times. These services have relationship with SDG No.10 (Reduce Inequalities), SDG No.11 (Sustainable Cities & Communities), SDG No.12 (Responsible Consumption & Production).

2.8: Utility, Licenses and Online Services:

In the present era of technology, majority of the services are available online for basic processing. Many utility services are also just on a call distance but requires basic set of skills. In order to venture into any business, there are some regulatory requirements which need to be fulfilled essentially. In order to save time and energy of the people, the facilitation support is given to the people at their door step. By doing this, people are finding themselves capable of doing the works they intend to, which otherwise used to be like long projects for them. Hence, this Division has relationship with the SDG No.10 (Reduce Inequalities).

2.9 Integrated Risk Management and Social Security: Apart from climate change and sustainability, special focus has been given on the Disaster Risk Reduction (DRR) including emergency services. When no one is there to listen a crying voice, Mission RIEV will not only listen but come forward to extend required support to the affected people. Capacity Building measures on DRR are being taken up by this Division in close coordination with the Advisory Boards. Apart from this, life, health & general insurances are also covered under the ambit of this Division and form the part of SDG. No. 11 (Sustainable cities & Communities).

2.10 Institutional Support And Area Adoption Service Division:

Institutional support refers to the part of economic environment of industry as well as operation of any social or cooperative entities. It covers need analysis of institutions like Societies, Companies, Cooperatives, Committees, Firms, etc. and provides support in Envisioning, Business Plan Formulation, Monitoring & Evaluation, Resource Planning, Auditing, Statutory and Regulatory Compliances, Technology Adoption and the like.

These services have direct relationship with the SDG No. 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG No. 16 (Peace, Justice and Strong Institutions) and SDG No. 17 (Partnership for the Goals).

2.11 Democratic And Electioneering Service Division:

The services under this Division primarily help in managing the democratic process of local authorities. In addition, these help in providing base line real time data; Conducting Assessment, Survey for identifying ideal and potential contestants; Facilitation support in manifesto preparation; Social Media Management and the like. Services of this division fall under SDG No. 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).

2.12 NRIs Support Services:

The main objectives of this division are to help the NRIs in protecting their rights in our country, to promote social welfare in India by facilitating NRIs & their relatives residing in India. Other services are: Extending all kinds of support required by the families and dependents of NRIs in India; expediting various regulatory tasks in India as required by NRIs; Facilitating NRIs in investment plans, business development, Philanthropy and business expansion. It will also facilitate in maintaining cultural and ethnic bonds with the NRIs especially with the new generation of the NRIs. These services have relationship with SDGs 10 (Reduced Inequalities) and SDGs 11 (Sustainable Cities and Communities).

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

केकैयी का वरदान भी 14 वर्षों का था.....

त्रिलोकी श्रीराम को इंसाफ मिलने में लग गए 500 साल

अब नहीं रहे कश्मीर व राम मंदिर निर्माण विवादित मुद्दे, मिली सामुहिक सराहना

केकैयी ने महाराज दशरथ से मंथरा के बहकावे में आकर अपने सुरक्षित तीन वरदान जब मांगे तो उसमें एक वरदान दशरथ के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। सत्ता भरत को सौंपने के अलावा श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास जब मांगा तो इस आघात से राजा दशरथ उभर न पाये। सतयुग का वो वनवास कलियुग के आरंभिक चरण में भारत में 500 से अधिक वर्षों का हो गया जिसमें अपने जन्मस्थान को लेकर ही हम तय नहीं कर पा रहे थे कि राम जन्म भूमि कौन सी है, किसकी है, क्या बाबर की बनाई मस्ज़िद ही वास्तव में वास्तविक थी या राममंदिर को तोड़ कर उस पर बनाई गई थी ? यह तय करने में एक लंबा अरसा बीत गया और हिंदुओं और सनातनी जिसे अपना तारणहार कहते हैं, उनके तारणहार को अपने ही घर में आने के लिए इतना लंबा समय लग गया। उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की बैंच ने एकमत से निर्णय देते हुए विवादित स्थल को रामजन्म भूमि बताते हुए करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं पर मोहर लगा दी और अब राममंदिर निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया।

सरकार की मंशा स्पष्ट : जनादेश का पालन हो

मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए जिससे देश में परिवर्तन की उम्मीद जगी। निर्णयों के अलावा कुछ आम इंसान को स्पर्श करती हुई योजनाओं/परियोजनाओं पर भी सरकार का रुख स्पष्ट रहा जिससे इस सरकार को जनता ने भारी बहुमत से दुबारा सत्ता की चाबी सौंप दी। नोटबंदी, जीएसटी, पाकिस्तान को जवाब आदि ऐसे मुद्दों ने सरकार को लोगों की पसंद बना दिया। प्रधानमंत्री इस बात को बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि इस देश का राजनीतिक तंत्र क्षेत्रिय दलों की जंज़ीरों से जकड़ा हुआ है और इसी के चलते गठबंधन में सरकारें बनती और बिगड़ती रहती है। अगर लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री और सरकार पर बना है तो यह समर्थन देश के चिरपरिचित मुद्दों और समस्याओं के निदान की ओर कड़े क़दमों को उठाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने इसमें देर नहीं की। देश का गृह मंत्रालय बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के हाथों सौंप कर बड़े निर्णयों में स्वयं मोदी ने प्रयास आरंभ किए और देश से विदेशों में भारत के लिए जुगाड़ की रणनीति अपनाई। कश्मीर और राममन्दिर निर्माण बीजेपी के लिए वैसे भी अब गले की फांस बनती जा रही थी। क्योंकि जनसंघ से बीजेपी के गठन के बाद जब केवल 2 सीटें ही थी, तब भी इन मुद्दों पर पार्टी दहाड़ती थी और जैसे-जैसे सत्ता के क़रीब आने के लिए संख्या बल बढ़ा, ये मुद्दे भी और गंभीर होते गए। देश के मतदाता भी कई बार यह भी कहने लगे कि बीजेपी मात्र चुनावी मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल करने के लिए इसके निदान के प्रति गंभीर नहीं है। लेकिन जिस धैर्य और समर्थन की सरकार को आवश्यकता थी वो अब मिल चुका था। सरकार की मंशा स्पष्ट थी इसलिए पहला प्रहार कश्मीर की

समस्या पर हुआ और धारा 370 और 35 ए को झटका देते हुए जम्मु-कश्मीर और लद्दाख को केन्द्र शासित राज्य बना दिया। रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की प्रशंसा देश से विदेशों तक हुई। कश्मीर में समस्या इतनी पाकिस्तान की ओर से नहीं थी जितनी भीतरघातियों से थी। इन अलगाववादियों को पहलें सरकारों से खुली छूट और मनमानी का जो लाईसैंस मिला हुआ था उससे कश्मीर एक अरसे से रक्तरंजित होता रहा और दोहरी नागरिकता ने इन आतंक और अलगाव के आकाओं को बादशाह बनाकर रखा हुआ था। सरकार ने कश्मीर को एक संविधान और एक झंडे तले लाकर इनकी कमर ही तोड़ दी। सारे अलगववादियों ने सोचा भी न होगा कि सरकार ऐसा क़दम भी उठा सकती है। कश्मीर आज भारत के संविधान में एक ही नियम के तहत अब विकास की राह पर अग्रसर है।

दूसरा मुद्दा राम मंदिर निर्माण और राम जन्म भूमि विवाद का था जो अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में तो था ही लेकिन इसमें मोदी सरकार का धैर्य प्रशंसा का पात्र है। स्वयंसेवक संघ और हिंदु संगठनों ने सरकार पर तीखे आलोचना के बाण चलाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। साधु-संतों ने तो सरकार की नाक में दम कर रखा था। एक ओर जहां देश का नेतृत्व मोदी के हाथों मे था तो उत्तर प्रदेश का साम्राज्य कट्टर हिदुवादी योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया में फलीभूत हो रहा है। ऐसे में साधु-संतों ने और इनके दबाव में हिंदुवादी संगठनों ने सरकार पर रामजन्म भूमि पर ही राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाकर निर्णय लेने का भारी दबाव बनाया। लेकिन मोदी ने अक्सर अपने संबोधनों में देश के सर्वोच्च न्यायालय पर आस्था रखते हुए इस मुद्दे पर एक भी शब्द नहीं कहा और कहा कि जो भी निर्णय होगा वो ही सर्वमान्य होगा। अदालत ने भी पूरी कोशिश की और कहा कि अदालत के बाहर सारे पक्ष आपस में बातचीत से समस्या को सुलझा लें तो बेहतर होगा। इस पर मुस्लिम पक्ष का समर्थन नहीं मिल सका। शिया पक्ष तो फिर भी रजामंदी करना चाहता था लेकिन सुन्नी पक्ष राजी नहीं हुआ। कई धर्मगुरुओं ने पहल की लेकिन परिणाम में कुछ भी हासिल न हुआ। अंततः न्यामूर्ति रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली पांच जजों वाली बैंच ने प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई आरंभ की और सारे पक्षों की दलीलें, गवाही एक तय समयसीमा में पूरी कर ऐतिहासिक निर्णय सुनवा दिया। निर्णय पर पूरा देश प्रतीक्षारत था। इसे करोड़ों लोगों ने सोशल मीडिया और टीवी पर एकटक देखा और सुना भी।

ऐतिहासिक निर्णय में बैंच ने स्पष्ट किया कि विवादित ज़मीन रामलला का जन्मस्थान ही है। साक्ष्यों के आधार पर इसे साबित करते हुए वहां सरकार को ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के लिए आदेश जारी किए। मस्ज़िद के लिए पांच एकड़ ज़मीन अन्यत्र देने पर भी सरकार को आदेश जारी किए। निर्मोही अखाड़ा जो कि रामलला का सेवादार बन कर सेवा करना चाहता था, उसे भी इससे बाहर कर दिया गया। यानि अब राम मंदिर का निर्माण सरकार के दिशा-निर्देशों और देख-रेख में होगा जिसके लिए ट्रस्ट की स्थापना की जाऐगी। सरकार ने जनादेश को समझते हुए बड़ी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने की क़वायद शुरु कर दी और इसी का परिणाम है कि अब अगले चुनाव बहुत पुराने पक चुके और सड़-गल चुके मुद्दों के बिना किसी और मुद्दें के साथ लड़े जाऐंगे। लोगों ने मोदी सरकार पर यह भरोसा जताया था कि सरकार खोखली राजनीति के लिए जिम्मेवार इन चिर मुद्दों को समाप्त कर विकास के लिए समुचित क़दम उठाऐगी जिसका प्रमाण सरकार ने यथासंभव देना आरंभ कर दिया। इससे एक बात तो यह भी साबित हो जाती है कि सरकार चाहे तो बेहतर और कुशल रणनीति को अपनाकर सही मंशा से देश का मार्गदर्शन करने में सार्थक पहल कर सकती है न कि मुद्दों को स्वार्थ की पनीरी बनाकर उलझाने के बाद सत्ता पर क़ाबिज़ होती रहे। हालांकि देश ने अब तक तो ऐसा ही मंज़र देखा था।

राम मंदिर/कश्मीर के नाम पर लगा रहा सरकारों का आना जाना....मोदी ने कूटनीति से सुलझाया

राम मंदिर निर्माण ऐसा नहीं है कि बीजेपी का पेटेंट मुद्दा रहा हो, कांग्रेस की सरकारों ने भी देश में करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाने में कोर-कसर न छोड़ी। 1984 के चुनावों में बीजेपी को मात्र दो सीटें ही मिली। हालांकि कांग्रेस ने ताबड़तोड़ सफलता हासिल की और जीत का आंकड़ा 400 सीटों के पार रहा। हालांकि विश्व हिन्दु परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने राम मंदिर की मुहिम को हवा दी थी लेकिन इसका असर चुनावों पर नहीं हुआ। केवल दो ही सीटें बीजेपी हासिल कर पाई। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति वोट पर कब्ज़ा कर लिया और भारी बहुमत से सरकार का गठन हुआ। हालांकि कुछ ही समय बाद राजीव गांधी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप भी लगे। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हिंदुओं को खुश करने के लिए कोशिशें शुरु कर दी। 1949 में अंदर रखी रामलला की मूर्ति की पूजा की अनुमति नहीं थी जिसे 1986 में मस्ज़िद के ताले खुलवाकर अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति दे दी गई। ये वो दौर था जब देश में पहली बार हिंदुओं ने नागरिक की तरह नहीं हिंदु की तरह देखना आरंभ कर दिया। 1989 में स्वयं राजीव गांधी ने चुनावों में हिदुओं को राम मंदिर निर्माण का सपना दिखाया था। सरकार यह जानती थी कि हिंदुओं को खुश किए बिना सत्ता में वापसी संभव नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर स्थाई रुख नहीं अपना सकी और लारेलप्पों के बाद बीजेपी ने इस मुद्दे पर एकजुटता के साथ पैरवी शुरु कर दी। और आगे चल कर बीजेपी की रेसिपी बन गई। उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार ने बड़ी खूब चुटकी लेते हुए कटाक्ष किया था कि शरद पूर्णिमा की रात खीर को छत पर रखा जाता है और सुबह उसे खाया जाता है जिसका गुण अमृत के समान होता है। कांग्रेस ने खीर बनाई भी, छत पर रखी भी लेकिन खा गई बीजेपी।

1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने राममंदिर के मुद्दे को भुनाते हुए 1989 में 85 सीटें जीत लीं। इस दौर में राम मंदिर मुद्दे पर लाल कृष्ण आडवाणी का क़द इतना बढ़ गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस मुद्दे पर मंडल कमीशन के आरक्षण को लागु करने की स्वीकृति दे दी। मंदिर बनाम मंडल के विवाद में जीत भाजपा की ही हुई और आडवाणी ने रथयात्रा से हिंदु अस्मिता को आगे रखते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए कारसेवकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का तीर चला दिया। वास्तव में लालकृष्ण आडवाणी की रथयात्रा के कारण ही बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान बना पाई थी।

1991 में मध्यावति चुनावों में पार्टी 120 सीटें जीत गई और सीटों का ये इज़ाफा हिंदु वोट का ध्रुवीकरण स्पष्ट ही दिख रहा था। उसी वर्ष उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। 6 सितंबर 1992 को बाबरी मस्ज़िद गिराने के साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकार तो गिरी ही, यह भी लगा कि बीजेपी का ये सफर भी यहीं तक था। उसके बाद वाजपेयी के करिश्माई नेतृत्व में पार्टी को संबल मिला और केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। इससे पार्टी में जान आई। 2004 और 2009 में बीजेपी ने शाईनिंग इंडिया का नारा देने के बाद भी सत्ता का मुंह नहीं देखा। 2014 में सारे समीकरण बदल गए और बीजेपी में एक लंबे समय के बाद गुजरात में विकास और शाईनिंग का डंका बजाने वाले नरेन्द्र मोदी जनमानस की आवाज़ बन गए और 2014 में प्रधानमंत्री भी। अब बड़े मुद्दों पर पूर्व में गर्जना करने वाले नरेन्द्र मोदी पर देश की निगाहें थी क्योंकि उन्होंने गाहे-बगाहे अपने संबोधनों में तत्कालीन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया था। अब बारी उनकी थी। वो चूके भी नहीं, जब-जब मौका मिला बड़े निर्णय लेकर सबको चौंका दिया। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं पाया कि ऐसा क़दम भारत उठा सकता है। इसी के चलते सरकार का दूसरा अवसर मिलते ही कश्मीर और राम मंदिर पर समाधान का बाण चलाया और एक ही झटके में दशकों से खड़ी और बड़ी इन समस्याओं को ख़त्म कर दिया।

आओ अब विकास की ओर बढ़ें

जो मुद्दें अब कैंसर हो चुके थे उन्हें लगभग ढांक से नीचे फेंक दिया गया है। और अब जो रह गए हैं उनको समाधान पर लाने के साथ ही देश के विकास को दिशा देने की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। श्रीराम का रामराज्य हम पुनः स्थापित तो करने की बात करते हैं लेकिन उनको स्थापित करने में ही सैंकड़ों वर्ष लग गए। गांधी जी का स्वराज या रामराज्य मिलकर आगे बढ़ने और आपसी मदभेदों से दूर, जाति, धर्म, संप्रदाय से उपर एक समान दृष्टि के साथ ही पूरा किया जा सकता है।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे विश्वास पर हिमाचल में करें निवेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा हिमाचल से खास तौर पर जुड़ाव है। इसलिए निवेशक यहां निवेश करने को लेकर मन में कोई संशय नहीं रखे बल्कि निवेश करते समय यह समझे कि वह मेरे यानी देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास कर निवेश कर रहे हैं।

मोदी ने आगे कहा कि हिमाचल की भाषा की बड़ी विविधता है। एक-दूसरे की बोलियां समझ नहीं आतीं, मगर एक-दूसरे से जबरदस्त जुड़ाव है। यहां साक्षरता दर भी बहुत ऊंची है। यहां के लोगों के भीतर एक स्वाभाविक उद्यमिता भाव है। देश के रक्षा क्षेत्र में हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं, जिनमें से कोई सेना में न हो। एक प्रकार से हिमाचल एक लघु भारत है। पूरे हिंदुस्तान का एक रूप है। पूरे भारत की यहां के लोगों में समझ है। यहां के लोग भारत की हर भाषा को समझते हैं। कोई तमिल तो कोई गुजराती बोल लेता है, क्योंकि वे देश भर में सेवाएं देते रहे हैं। यहां के युवाओं से अधिक से अधिक अवसर लें और इसका लाभ लें।

उप–राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को किया सम्मानित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन में भारत के उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें राज्य में संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा देने के लिए प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत केवल हमारे देश की भाषा नहीं, बल्कि अपनी समृद्धता के कारण यह एक वैश्विक भाषा है। राज्य सरकार प्रदेश में संस्कृत भाषा के विस्तार के लिए राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी समृद्ध धरोहर और पहचान के साथ जुड़ी है, इसलिए इसे बढ़ावा और संरक्षण देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार संस्कृत भाषा को और अधिक लोकप्रिय बनाने के प्रयास करेगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसे बोलने और संवाद करने के लिए अपनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाला देश है और हमें इसे संरक्षित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए। कोई भी देश अपनी समृद्ध विरासत और मूल्यों की अनदेखी कर प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कहा कि हमें

आधुनिक सोच और मूल्यों को अपनाने के साथ अपने संस्कार और संस्कृति पर भी गर्व करना चाहिए और इनकी अनदेखी करके हासिल की गई सफलता वास्तविक अर्थों में सफलता नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने सम्मान के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया और इस आयोजन के लिए सराहना की।

मकान की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाना अब महंगा, सरकार ने घटाई सब्सिडी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बिजली बिलों में कटौती और कमाई का साधन बढ़ाने के लिए घर की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने की योजना बनाकर बैठे लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सोलर रूफ टहप पावर प्लांट लगाने के लिए मिलने वाली 70 फीसदी सब्सिडी को केंद्र ने 30 से 50 फीसदी तक घटा दिया है। तीन किलोवॉट से बड़े प्लांट लगाने पर अब सिर्फ 20 फीसदी ही छूट मिलेगी। तीन किलोवॉट तक के प्लांट पर 40 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान निवेशकों ने शुक्रवार को केंद्रीय अधिकारियों के समक्ष सब्सिडी घटाने को लेकर नाराजगी जताई। हिमाचल सरकार ने भी यह मामला उठाया।

हिम ऊर्जा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृतिका ने कहा कि हिमाचल में योजना काफी सफल रही है। सब्सिडी को दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। केंद्रीय अधिकारियों ने मामले को सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया है।

'मनोहर यादों' से गेयटी हुआ गुलजार

राजधानी के ऐतिहासिक थियेटर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया नाट्य उत्सव का आगाज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला वर्ष 1887 में गोथिक शैली में बने गेयटी थिएटर में स्वर्गीय मनोहर सिंह स्मृति में नाट्य उत्सव का आगाज हो गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संस्कृति को मजबूती देने के लिए सरकार कई अहम कदम उठा रही है, जिसमें फिल्म पॉलिसी इसमें से एक है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद थे। वहीं भाषा संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह भी कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि रंगमंच की मजबूती के लिए इस तरह के कार्यक्रम काफी अहम योगदान देते हैं। फिलहाल आयोजित इस कार्यक्रम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से तीन

मुख्यनाटकों का मंचन किया जाने वाला है। इस बार कार्यक्रम की खास बात यह भी है कि एनएसडी के निदेशक सुरेश शर्मा स्वयं गेयटी आए हैं।

हिमाचल प्रदेश निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य: पीयूष गोयल

93 हजार करोड़ रुपये निवेश क्षमता के 614 एमओयू हस्ताक्षरित किए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

धर्मशाला में बीते दिनों आयोजित राईजिंग हिमाचलः ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की विविधता राज्य को निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बनाती है। उन्होंने कहा कि यह उद्यमियों के लिए राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों से ही सम्भव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में उद्यमियों की सहभागिता दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश ने विकास की दिशा में एक ऊंची उड़ान भरी है और विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक सौन्दर्य, शांत वातावरण, वनस्पति एवं जैव सम्पदा, जैव विविधता, बर्फीले पहाड़, मनोरम वादियां, अनछुए जंगल और विभिन्न परम्पराएं एवं सांस्कृतिक धरोहर पर्यटनों को हिमाचल प्रदेश को स्वर्ग बनाती हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से पर्यटन क्षेत्र में सम्भावनाओं को तलाशने का आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर है और राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के लिए की गई पहल सराहनयी है। राज्य सरकार की मानव अनुकूल नीतियां प्रदेश में निवेश को आकर्षित करेंगी। उन्होंने इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इससे न केवल भारत, बल्कि विश्वभर से निवेश के दरवाजे खुलेंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और पिछले पांच वर्षों में हमने एक ट्रिलियन डॉलर इसमें जोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार कड़ी मेहनत कर रही है।

आगामी जनवरी माह से बनेगे नए कार्ड: विपिन परमार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ महत्त्वाकांक्षी हिमकेयर योजना के तहत नए कार्ड आगामी जनवरी माह से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमकेयर के तहत अब तक 5.50 लाख परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है तथा एक वर्ष पुराने कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो परिवार आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए उनके लिए हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थियों को पांच लाख रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब तक हिमकेयर योजना के अंतर्गत 47,882 लाभार्थियों को 46.25 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जा चुका है।

अब 2450 मीटर लंबा होगा कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कांगड़ा एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई अब 1920 मीटर नहीं बल्कि 2450 मीटर तक बढ़ाई जाएगी। कांगड़ा के विस्तारीकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर कांगड़ा चंबा लोकसभा सांसद किशन कपूर की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक किशोर कुमार, डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति, एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन, एसडीएम कांगड़ा जतिन लाल, एसडीएम जगन ठाकुर सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में चर्चा हुई कि 1920 मीटर के रनवे में भी बड़ा जहाज उतारना मुश्किल होगा। अगर कांगड़ा एयरपोर्ट पर बड़ा जहाज उतारना है तो रनवे 2400 मीटर से ज्यादा करना होगा। बैठक में कांगड़ा एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के निदेशक को दोबारा से फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी सर्वे करने के लिए कहा गया। बैठक के बाद डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक को दोबारा सर्वे के लिए आधिकारिक पत्र भी जारी कर दिया। नए सर्वे के बाद ही प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहरण के लिए अधिसूचना जारी करेगी। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया को सर्वे करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। पहले के सर्वे में जिला प्रशासन ने करीब 30 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करनी थी।

आलू बीच के दामों में आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आलू बीज के दाम ने किसानों को झटका दे दिया है। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल आलू का बीज आठ सौ रुपये महंगा मिलेगा। लाहौल के आलू का बीज लेने के लिए किसानों को इस बार 3800 रुपये प्रति क्विंटल खर्च करने होंगे। पिछले साल बीज 3000 रुपये क्विंटल बिका था। हिमाचल के कई इलाकों में आलू की फसल बड़े पैमाने पर होती है।

यह किसानों की आर्थिकी का जरिया है, लेकिन बीज के दाम में एक साथ 800 रुपये की बढ़ोतरी से किसानों को झटका लगा है। कोटखाई में पैदा होने वाली आलू के बीज पर प्रतिबंध के बाद विभाग ने लाहौल-स्पीति से आलू का बीज मंगवाया है। सीपीआरआई के आलू बीज में भी वायरस मिलने के बाद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के बाद सीपीआरआई मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में जुटा है। विभाग का कहना है कि डिमांड के अनुसार ही आलू का बीज ब्लॉकों में भेजा जाएगा। प्रदेश काफी संख्या में किसान सीधे तौर पर सीपीआरआई से बीज की खरीदारी करते थे, सीपीआरआई के पास बीज न होने से किसानों को बीज के लिए कृषि विभाग पर निर्भर रहना पड़ेगा। वायरस को हटाने के लिए अभी टीम को दो साल और लग सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा किसानों को डिमांड के अनुसार ही आलू का बीज दिया जाएगा। लाहौल-स्पीति से लाया गया आलू का बीज किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

हिमाचल में अब डेढ़ सौ वर्ग मीटर में भी लग सकेंगे उद्योग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में उद्योगपति अब 150 से 500 वर्ग मीटर जगह पर भी लघु उद्योग लगा सकेंगे। उद्योगपतियों को राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हिमाचल में कारोबारी ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकें, इसको लेकर यह पहल की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग इन उद्योगों के आधारभूत ढांचे के निर्माण को मंजूरी देगा। हिमाचल में अभी छोटे उद्योग स्थापित नहीं किए जा रहे हैं।

सरकार का मानना है कि लघु उद्योग स्थापित किए जाने से जगह कम उपयोग में लाई जा सकेगी। दूसरे हिमाचल के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। उद्योग विभाग की मानें तो पहले भी छोटे-छोटे उद्योगों को लगाने की मंजूरियां दी गई हैं। बद्दी, नालागढ़, कालाअंब, शोघी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों ने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। इनमें ब्लेड, सूई, धागा तैयार किए जा रहे हैं।

उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को आधारभूत ढांचा स्वीकृत कराने के लिए एक बार कार्यालय में आवेदन करना होगा। टीसीपी के कर्मचारी एक बार मौके का निरीक्षण करेंगे। भवन निर्माण के साथ-साथ लोगों को व्यवसायिक बिजली और पानी मुहैया कराया जाएगा।

प्रदेश में नशा निवारण विशेष अभियान आरम्भ

मुख्यमंत्री ने की अभियान को जन आनंदोलन में बदलने की अपील

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि नशे की बुराई से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है तथा नशे के दुष्प्रभावों के बारे जागरूकता लाने के लिए एक जन आनंदोलन आरम्भ किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा रिज मैदान पर 'नशे के विरुद्ध' आरम्भ किए गए विशेष अभियान के अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। नशा निवारण और शराबबंदी का यह विशेष अभियान प्रदेश के सभी जिलों में आरम्भ किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज से इस बुराई को मिटाने के लिए प्रदेश सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि एक माह तक चलने वाला यह अभियान इस रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान औपचारिकता मात्र ही नहीं है बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के बेहतर समन्वय के द्वारा इन प्रयासों को फलीभूत किया जा सकता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि लोगों को जागरूक करने में चिकित्सक अपनी अहम भूमिका दे सकते हैं। इसी प्रकार, अध्यापक विद्यार्थियों को जागरूक कर नशे से दूर रहने को प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को नशे के माफिया से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि नशा तस्करों व इससे जुड़े लोगों के जाल को तोड़ा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि यह उनके द्वारा किए गए प्रयासों के ही परिणाम है कि नशे के विरुद्ध अभियान चलाने और कारगर नीति अपनाने के लिए सात उत्तरी राज्य एक साथ मिले।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मिशन गगनयानः रुस में प्रशिक्षण हेतु 12 संभावित यात्रियों को चुना गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के अनुसार, इसरो के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव पेशेवर तरीके से किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना के बारह लोगों को गगनयान परियोजना हेतु संभावित यात्री के तौर पर चुना गया है।

अंतरिक्ष यात्रा हेतु भारतीय वायु सेना के कर्मियों के चयन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है। गगनयान मिशन के अंतर्गत करीब दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को मिलेगा वर्ष 2019 का व्यास सम्मान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नासिरा शर्मा को साल 2014 में प्रकाशित उनके उपन्यास 'कागज की नाव' के लिए वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान हरेक साल भारतीय भाषाओं के लेखक तथा कवि को दिया जाता है। प्रसिद्ध आलोचक डॉ. रामविलास शर्मा को वर्ष 1991 में पहला व्यास सम्मान मिला था। यह पुरस्कार साल 2018 के लिए चर्चित कवि लीलाधरी जगूड़ी को दिया गया था। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किये गये योगदान हेतु दिया जाता है।

केंद्र सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाने का फैसला लिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अब सिर्फ एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ही रहेगी। क्योंकि इससे पहले एसपीजी की सुरक्षा केवल चार लोगों के पास थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ - साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी का नाम शामिल था। सरकार द्वारा सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और अगर जरूरत हो तो उस आधार पर उसे कम या अधिक किया जाता है। एसपीजी सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर होता है।

UCCN: मुंबई और हैदराबाद सूची में शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूएनएनसीसी सूची में मुंबई को फिल्मों के क्रिएटिव शहर का सदस्य घोषित किया है। इसी प्रकार हैदराबाद को बिरयानी और अन्य स्वादिष्ट पकवानों के लिए व्यंजनों की श्रेणी में क्रिएटिव शहर के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को ने यूएनएनसीसी सूची में दोनों शहरों को दुनिया भर के 64 अन्य शहरों सहित इस सूची में जोड़ा है। अब तक इस सूची में कुल 246 शहर जुड़ चुके हैं।

Trace Bribery Risk Matrix – 2019 दक्षिण एशिया में बांग्लादेश शीर्ष पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

Trace Bribery Risk Matrix के मुताबिक, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में रिश्वत के लेन-देन का आशंका सबसे अधिक है। इस मैट्रिक्स में बांग्लादेश का कुल रिस्क स्कोर 72 है जो पिछले वर्ष की तुलना में दो अंक ज्यादा है। इस सूची में बांग्लादेश को 178वां स्थान मिला है तथा भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रिश्वत लेन-देन की संभावनाएं मौजूद हैं। इसमें इस वर्ष 200 देशों की सूची जारी की गई है।

दक्षिण एशिया के भूटान में रिश्वतखोरी का आशंका सबसे कम है। भूटान को इस सूची में 52वें स्थान पर रखा गया है। न्यूजीलैंड को इस सूची में पहले स्थान पर है तथा सोमालिया 200वें स्थान पर रखा गया है। जिस देश को इस सूची में सबसे ज्यादा रैंकिंग दी गई है वे सबसे अधिक प्रभावित देश है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद से दिया इस्तीफा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अभी तक महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 09 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर असमंजस और बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी तथा शिवसेना गठबंधन को विधानसभा चुनाव परिणामों में स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन दोनों दलों के बीच सरकार बनाने को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद पांच साल तक साथ देने हेतु सभी का शुक्रिया अदा किया।

वॉएजर-2 सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला दूसरा यान बना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नासा के नाम एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। नासा का वॉएजर-2 यान चार दशक से लंबे सफर के बाद सौरमंडल की परिधि के बाहर पहुंचने वाला दूसरा यान बन गया है। नासा का ही वॉएजर-1 इससे पहले इस सीमा के पार पहुंचा था। वॉएजर-2 एक अमेरिकी मानव रहित अंतरग्रहीय शोध यान है। नासा द्वारा वॉएजर-2 को 20 अगस्त 1977 को प्रक्षेपित किया गया था। दोनों यान

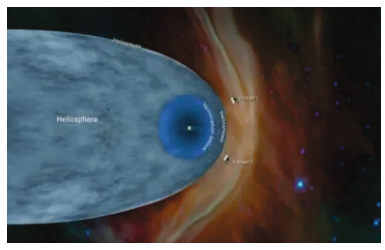

को उद्देश्य और पथ में अंतर के साथ धरती से परे ग्रहों व अंतरिक्ष के अध्ययन हेतु लांच किया गया था।

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर लगा प्रतिबंध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई शहरों और क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए 04 नवंबर 2019 को शीर्ष अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा की गई। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जारी किया है जो क्षेत्र में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, पटना में पीएम 2.5 का स्तर 428 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के स्तर पर पहुंच गया है।

वैश्विक जलवायु आपातकाल पर 153 देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने की संयुक्त घोषणा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बायोसाइंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत से 69 सहित 11,258 हस्ताक्षरकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के वर्तमान लक्षण को प्रस्तुत किया है। इससे निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले प्रभावी कदमों का भी उल्लेख किया है।

वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पर्यावरण को लेकर विश्व को अब गंभीर कदम उठाने की बहुत जरूरत है।

वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट में कहा की हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम किसी भी ऐसे

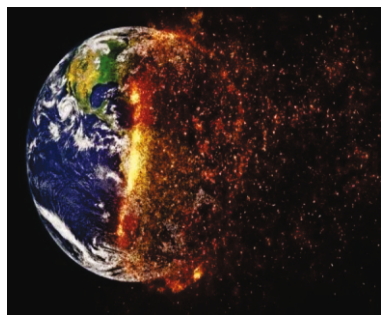

संकट के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करें जिससे महान अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा हो।

आरसीईपी समझौता से अलग हुआ है भारत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विषयों का सही समाधान नहीं दिखने पर आरसीपी समझौते से बाहर रहना ही बेहतर समझा। केंद्र सरकार के फैसले का भारत के सभी विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया, जो इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ थे। आरसीईपी (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) एक व्यापार समझौता है।

यह सदस्य देशों को एक - दूसरे के साथ व्यापार करने की सहूलियत प्रदान करता है। भारत में आरसीईपी को लेकर बहुत लंबे समय से चिंताएं जताई जा रही थीं। किसान और व्यापारी संगठन इसका विरोध कर रहे थे।

जम्मू – कश्मीर के विभाजन के बाद सरकार ने भारत का नया नक्शा जारी किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद भारत का एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को विधिवत अस्तित्व में आ गये थे। नए नक्शे के अनुसार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिलों को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बताया गया है। इन दोनों जिलों

सर्वे जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी मानचित्र

सहित जम्मू और कश्मीर में कुल 22 जिले होंगे। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र में 22 जिले शामिल हैं। लद्दाख में दो जिले कारगिल और लेह शामिल हैं।

भारत और जर्मनी ने 17 एमओयू और पांच संयुक्त घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने प्रवास, आयुर्वेद और योग, व्यावसायिक रोगों, समुद्री प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप सहित 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

इस दौरान पांच संयुक्त घोषणा पत्रों का भी आदान - प्रदान किया गया जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी विकास के लिए साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और समुद्री कूड़े के निपटान हेतु सहयोग शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन भारत में स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकता: लैंसेट रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यह रिपोर्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित की गई। भारत में आने वाले वक्त में जलवायु परिवर्तन के वजह से एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। रिपोर्ट के द्वारा इस समस्या से कुपोषण जैसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार इस वजह से साथ ही हैजा और उसके कारण होने वाला संक्रमण बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से मुख्य रूप से बच्चों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गंभीर संकट पैदा हो सकता है।

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वियना समझौते का उल्लंघन किया: आसीजे अध्यक्ष

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आईसीसे के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी युसूफ ने कुलभूषण जाधव मामले में संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने इस मामले में

आवश्यक कदम नहीं उठाए। इसके अतिरिक्त, जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का भी आदेश दिया गया। भारत इस अधिकार के लिए लंबे समय से कह रहा था।

भारत और सऊदी अरब ने उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत और सऊदी अरब ने उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है। इस परिषद की अगुआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे और यह प्रत्येक दो साल के अंतराल पर बैठक आयोजित करेगी। रणनीतिक साझेदारी परिषद के माध्यम से सभी प्रकार के आतंकवाद और द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सऊदी अरब में रुपे कार्ड शुरू करने के संबंध में भी एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

पश्चिम बंगाल ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सरकार ने तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने पर होने वाले दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने हेतु यह कदम उठाया है। यह पाया गया कि न केवल वयस्क बल्कि नाबालिग भी गुटखा और पान मसाले का सेवन कर रहे थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार, राज्य में गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

विश्व भर में गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले 65 प्रतिशत लोग भारत में

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राष्ट्रीय एकता दिवस 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू - कश्मीर के एकीकरण को वल्लभभाई पटेल को समर्पित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है।

जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर, जम्मू और कश्मीर राज्य में धारा 370 वापस लेने का निर्णय सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित किया।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वल्लभभाई पटेल को दर्शाती है। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे।

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वियना समझौते का उल्लंघन किया–ICJ अध्यक्ष

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी युसूफ ने कुलभूषण जाधव मामले में संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। अब्दुलकवी युसूफ ने 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मुख ICJ की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी दी।

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा 17 जुलाई को दिए गये फैसले में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाकिस्तान को वियना संधि के नियम-36 के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए पाया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने इस मामले में आवश्यक कदम नहीं उठाए।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अपने फैसले में पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड दिए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का भी आदेश दिया। भारत इस अधिकार के लिए लंबे समय से कह रहा था और ICJ का यह फैसला भारत की कूटनीतिक जीत को दर्शाता है।

ICJ ने 17 जुलाई 2019 को दिए गये अपने फैसले में कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को उसे दी गई मौत की सजा की समीक्षा करने और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

कुलभूषण जाधव को कथित तौर पर 'जासूसी और आतंकवाद' के आरोप में 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का आरोप है कि जाधव ने कथित रूप से ईरान से देश में प्रवेश किया था। पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कुलभूषण जाधव को 10 अप्रैल, 2017 को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थीं।

भारत और जर्मनी ने 17 एमओयू और पांच संयुक्त घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किये

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत और जर्मनी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की दो दिवसीय भारत यात्रा के दौरान प्रवास, आयुर्वेद और योग, व्यावसायिक रोगों, समुद्री प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप सहित 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों राष्ट्रों ने पांच संयुक्त घोषणा पत्रों का भी आदान-प्रदान किया जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी विकास के लिए साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और समुद्री कूड़े के निपटान हेतु सहयोग शामिल हैं।

जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ 5वीं अंतर-सरकारी वार्ता की सह-अध्यक्षता के लिए भारत का दौरा किया। उनके साथ शीर्ष स्तर के मंत्री और एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया था। यात्रा के दौरान, जर्मन चांसलर ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। जर्मन चांसलर और पीएम नरेंद्र मोदी ने वार्ता के समापन के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया।

भारत–उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाने हेतु तीन समझौतों पर हस्ताक्षर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने सैन्य संबंधों में सहयोग बढ़ाने के लिए उज्बेकिस्तान के साथ तीन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल निजामोविच ने 02 नवंबर 2019 को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 18वीं बैठक में हिस्सा लेने के बाद द्विपक्षीय रक्षा वार्ता की।

भारतीय रक्षा मंत्री और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों देश उज्बेकिस्तान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के अनुरूप, रक्षा में अपने जुड़ाव के स्तर को बढ़ाने हेतु सहयोग करना तथा साथ काम करना जारी रखेंगे। दोनों देश आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में अपना आदान-प्रदान और बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे।

ईरान ने नया परमाणु रिएक्टर बनाने का कार्य शुरु किया, रुस का मिलेगा सहयोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ईरान ने हाल ही में बुशहर में अपने दूसरे परमाणु बिजलीघर में काम शुरू कर दिया। 2015 में अमेरिका सहित दुनिया के प्रमुख देशों के साथ हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान ने इस बिजलीघर में काम रोक दिया था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समझौते से पीछे हट जाने और प्रतिबंध लगा देने से ईरान अब परमाणु क्षमता हासिल करने के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। हालांकि परमाणु हथियार बनाने के लक्ष्य से अभी वह काफी दूर है।

ईरान ने परमाणु बिजलीघर में दूसरे रिएक्टर के लिए निर्माण का कार्य अपने तेल बिक्री पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद शुरू किया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने कहा, समझौता हमने नहीं तोड़ा है। समझौता अमेरिका ने एकतरफा फैसले के तहत तोड़ा है। अब हम अपनी जरूरतों के मुताबिक परमाणु क्षमता विकसित कर रहे हैं। बुशहर में रूस का यूरेनियम इस्तेमाल होता है और उसकी निगरानी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करती है। ईरान ने बुशहर में यूरेनियम को 4.5 प्रतिशत तक शोधित करने का लक्ष्य रखा है जबकि अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते में उसे 3.67

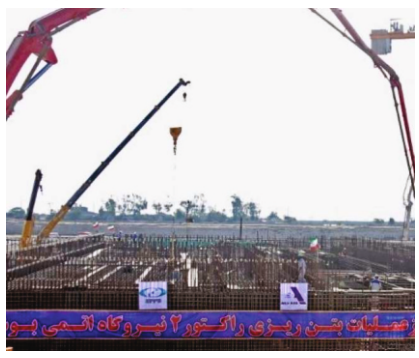

प्रतिशत शोधन की अनुमति मिली थी। परमाणु हथियार बनाने के लिए करीब 90 प्रतिशत शुद्ध यूरेनियम की जरूरत होती है जिससे ईरान अभी काफी दूर है।

1994 का शांति समझौता टूटा: जार्डन इजरायल से वापस लेगा पट्टे पर ली गई जमीन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जार्डन के सुल्तान ने हाल ही में घोषणा की कि इजरायल द्वारा पट्टे पर ली गई जमीन के दो टुकड़े जार्डन वापिस ले रहा है। दोनों देशों ने इसे अपने ऐतिहासिक शांति समझौते की 25वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया है। जैसे ही पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, वैसे ही सीमा पर फाटक बंद कर दिए गए। एएफपी ने बताया कि इजरायल को इस भूमि पर प्रवेश से रोक दिया गया। इसे जॉर्डन और इजरायल के बीच बिगड़ते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा था।

इजराइल का 70 वर्षो से अधिक समय से कृषि भूमि पर कब्जा है। 1994 के शांति समझौते के तहत इन क्षेत्रों को इस धारणा के साथ पट्टे पर देने की अनुमति दी गई थी कि इसे एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। इजराइल को समाधान मिलने की उम्मीद थी। लेकिन सुल्तान की घोषणा से इसके खत्म होने और जार्डन के इसी जल्द इलाके पर नियंत्रण कर लेने के आसार हैं।

बता दें कि 1994 की शांति संधि के तहत इजरायल के किसान नहरईम और तजोफर के जार्डन क्षेत्रों में भूमि पर खेती कर सकते थे। इसे अरबी में बाकुरा और गरम के रूप में जाना जाता है।

पाकिस्तान में मौलाना का जंग-ए-ऐलान, इमरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की खाई कसम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान में पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग को लेकर चलाए जा रहे आजादी मार्च की अगुवाई कर रहे जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में आजादी के दौरान मौलाना ने रविवार को सिट-ऑफ के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, युद्ध जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हट सकते। सभी राजनीतिक दल हमारे संपर्क में हैं।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, रहमान ने कहा कि जब उन्होंने बात की थी, तब भी विपक्षी दल कार्रवाई के अगले कदम के लिए बात कर रहे थे। मौलाना ने कहा कि कहा कि हम सभी नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दोहराया कि इमरान खान सरकार ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।

फिलहाल पाकिस्तान में आजादी मार्च जारी है। इसके आने वाले वक्त में और ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पीएम इमरान खान के इस्तीफे की मांग और तेज हो सकती है।

बुलबुल तूफान से बांग्लादेश में भारी तबाही

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चक्रवाती तुफान बुलबुल ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। तूफान की चपेट में आने से छह लोगों की मौत हो गई है, जबकि 36 मछुआरों के लापता होने की खबर है। अधिकारियों कि तूफान से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, जिसकी वजह से कम लोगों की जान गई।

प्रशासन के मुताबिक चक्रवात बुलबुल की वजह से लगभग 30 लोगों घायल हुए हैं और 6 हजार से ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। मारे गए छह में से पांच लोगों की मौत पेड़ों के गिरने की वजह से हुई है।

दक्षिणी भोला जिले के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मछली पकड़ने गई दो नौकाएं अभी भी लापता हैं। परिवार के लोग नवा में मौजूद लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। दक्षिण-पूर्व बांग्लादेश के शिविरों में किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, जहां पड़ोसी देश म्यांमार के हजारों शरणार्थी रह रहे हैं।

तूफान के आने से पहले तक बांग्लादेश के 13 तटीय जिलों में रह रहे 20 लाख से ज्यादा लोगों को लगभग 5,558 शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया।

अधिकारियों के मुताबिक तुफान के वक्त हवा की गति 100 से 120 किमी प्रति घंटे के बीच तक थी। भारी बरिश की वजह से कुछ निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। फिलहाल हवा की गति अब घटकर 70 से 80 किमी प्रति घंटे तक हो गई है।

आपदा प्रबंधन और राहत के मंत्री एनामुर रहमान ने रॉयटर्स को बताया कि फिलहाल सामान्य स्थिति होने में कुछ दिन का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि लगभग 1200 घरेलू पर्यटक कॉक्स बाजार जिले में सेंट मार्टिन द्वीप पर फंस गए थे। उन सभी लोगों को जल्द बचा लिया जाएगा।

सीरिया में 500 अमेरिकी सैनिक रहेंगे बरकरार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सीरिया से पूरी तरह से अमेरिकी सेना नहीं हटेगी। यहां 500 सैनिक बरकरार रहेंगे। एक शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्धग्रस्त देश सीरिया से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया था।

ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने कहा कि युद्धग्रस्त देश में अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे। इनकी संख्या एक हजार से कम 5 सौ से 6 सौ तक होगी। पिछले महीने ट्रंप ने सीरिया से सैन्य वापसी अचानक घोषणा की थी। इसी के बाद अमेरिकी-सहयोगी कुर्द लड़ाकों पर तुर्की ने हमला तेज कर दिया था। इस फैसले को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई। कहा गया इससे इस्लामिक स्टेट समूह मजबूत होगा और उसके खिलाफ अमेरिका की लड़ाई पर असर पड़ेगा।

बोलिविया में राजनीतिक संकट: मेक्सिको ने बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को शरण दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मोरालेस बोलीविया की मूल निवासी आबादी के राष्ट्रपति बनने वाले पहले सदस्य थे। वे 13 साल 09 महीने तक सत्ता में रहे जो बोलीविया के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यकाल है। उन्होंने पिछले महीने बोलीविया में जो चुनाव हुए थे उनमें चौथी बार जीतने का दावा किया था। मेक्सिको ने बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस को देश में शरण दी है। उन्होंने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सेना और जनता के बढ़ते दबाव के बीच 10 नवंबर 2019 को इस्तीफा दे दिया था। मेक्सिको सरकार ने कहा कि शरण मानवीय आधार पर दिया गया है, क्योंकि बोलीविया में इवो मोरालेस की जान को खतरा था।

विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपने विरुद्ध जबरदस्त विरोध के कारण इवो मोरालेस को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था। उन्होंने मेक्सिको की वायुसेना के विमान से बोलीविया छोड़ दिया। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुएल लोपेज ओबराडोर ने भी इस्तीफा देने का निर्णय के लिए उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा की मोरालेस के इस साहसिक कदम से बोलीविया की जनता पर से संकट टल गया।

जेयर बोल्सोनारो होंगें भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के होंगे मुख्य अतिथि

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री मोदी ने जेयर बोल्सोनारो को यह न्यौता ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अगले साल (2020) भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। जेयर बोल्सोनारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते को स्वीकार कर लिया है। भारत में 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जेयर बोल्सोनारो को यह न्यौता ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति की ओर से निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का पद भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- भारत का वह शहर जिसे यूनेस्को की यूएनसीसी सूची में पाक - कला श्रेणी में शामिल किया गया है - हैदराबाद
- वह देश जिसने हाल ही में अधिकारिक रूप से 5जी नेटवर्क लॉन्च किया है - चीन
- जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किये गये समझौतों की संख्या - 17
- भारत का वह शहर जहां प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है - दिल्ली
- भारतीय खिलाड़ी शिवा थापा और पूजा रानी द्वारा ओलिंपिक टेस्ट में जीते गये पदक - स्वर्ण पदक
- वह दिन जब हरियाणा स्थापना दिवस मनाया जाता है - 01 नवंबर
- वह टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने Fitbit का अधिग्रहण कर लिया है - गूगल
- भारत और उजबेकिस्तान के मध्य नवंबर 2019 में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है - Dustilk - 2019
- भारत का पड़ोसी देश जहां 'अफ्रीकन स्वाइन फीवर' के मामले सामने आये हैं - चीन
- वह राज्य जिसने बिहार और राजस्थान के बाद गुटखा और पान मसाले पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने का निर्णय लिया है - पश्चिम बंगाल
- 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में जिस शहर में आरंभ हुआ - बैंकॉक
- वह शिक्षण संस्थान जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में Alumni Endowment Fund लॉन्च किया है - आईआईटी दिल्ली
- सीपीआई के पूर्व सांसद और दिग्गज वामपंथी नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है - गुरुदास दासगुप्ता
- चिली द्वारा COP25 सम्मेलन का आयोजन रद्द करने के बाद वह देश जिसने इसका आयोजन करने की घोषणा की है - स्पेन
- एरिट्रिया और सेंट किट्स एंड नेविस नामक दो देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर गठबंधन में शामिल कुल देशों की संख्या है - 83
- वह एजुकेशनल इंस्टिट्यूट जिसने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार की है - आईआईटी हैदराबाद
- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद - 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर रखा गया है - ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर
- इन्हें हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया - लीलाधर जगूरी
- वह देश जिसने बड़े स्तर पर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों के कारण वहां आयोजित होने वाले COP25 और APEC शिखर सम्मेलन के अयोजन को रद्द कर दिया है - चिली
- वह दिन जब राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है - 31 अक्तूबर
- इन्होने हाल ही में लद्दाख के पहले उप-राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की - आरके माथुर
- नेशनल हेल्थ प्रोफाइल - 2019 के अनुसार भारत में लोगों की जीवन प्रत्याशा वर्ष 1970–1975 की तुलना में 49.7 से बढ़कर अब हो गई है - 68.7
- प्रत्येक वर्ष भारत में 31 अक्तूबर को जिस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है - इंदिरा गाँधी
- अरब सागर से उठे चक्रवात का नाम जिसके लक्षद्वीप से होकर गुजरने की घोषणा की गई है - MAHA
- वह राज्य जिसके लोकनृत्य भओना (Bhaona) के अंग्रेजी संस्करण का आयोजन आबू धाबी में किया गया - असम
- इन्होने हाल ही में नॉर्डिक परिषद का पर्यावरण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया - ग्रेटा थनबर्ग
- वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसने मानसिक अस्वस्थता के चलते खेल से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने की घोषणा की है - ग्लेन मैक्सवेल
- वह देश जिसके साथ भारत ने हाल ही में उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना की है - सऊदी अरब
- उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू द्वारा हाल ही संसदीय सुधार हेतु इतने सूत्रीय चार्टर पेश किया गया - 15
- हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू (एचबीआर) द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सीईओ की 2019 की सूची में शामिल भारतीय मूल के सीईओ की संख्या है - 3
- बांग्लादेश का वह क्रिकेटर जिसपर हाल ही में आईसीसी द्वारा दो साल का बैन लगा दिया गया है - शाकिब अल हसन
- कश्मीरी सेब उत्पादकों की मदद के लिये जिस राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था बिस्कोमान ने राज्य में कम मूल्य पर कश्मीरी सेब के विक्रय की पहल की है - बिहार
- वह स्थान जहां 31 अक्तूबर 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' पर्व का आयोजन किया गया - नई दिल्ली
- वह देश जिसने भारत के सीमावर्ती राज्यों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिये मणिपुर में नदी पर नये पुल के निर्माण की घोषणा की - म्यांमार
- वह भारतीय एयरलाइन्स जिसने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह 'एक ओंकार' बनाया है - एयर इंडिया
- वह देश जिसमें वॉट्सऐप, फेसबुक पर मेसेज और कॉल करने के लिए टैक्स लगाने का ऐलान किया गया था जिसके विरोध में हुए प्रदर्शनों के चलते वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा - लेबनान
- इन्हें हाल ही में भारत का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है - जस्टिस एस ए बोबडे
- आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना का नाम जिसे अमेरिकी सेना द्वारा एक विशेष अभियान में मारा गया - अबू बकर अल - बगदादी
- कानून मंत्रालय द्वारा नियमों में संशोधन के अनुसार इतनी आयु से अधिक के लोग अब पोस्टल बैलट का उपयोग कर सकेंगे - 80
- यूरोपीयन यूनियन एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारत पहुंचा है, उसमें लोगों की संख्या थी - 27
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिस योजना को लॉन्च किया है - कन्या सुमंगल योजना
- भारत और फ्रांस के बीच इस नाम से 31 अक्टूबर को संयुक्त सैन्य अभ्यास आरंभ किया गया - शक्ति - 2019
- वह देश जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि जाहिर की है - फिलीपींस
- पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर के दूसरी ओर करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल करके पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गये इमिग्रेशन काउंटर्स की संख्या है - 80
- वह देश जिसके राष्ट्रपति सेबेस्टिन पिन्येरा ने पूरी कैबिनेट को निलंबित कर दिया है - चिली
- नासा के जिस यान ने 42 वर्षों की यात्रा के बाद नवंबर 2019 में सूर्य की परिधि तक पहुँचने का रिकॉर्ड कायम किया है - Voyager-2
- हाल ही में भारत के जिस पड़ोसी देश ने अपने सभी सातों प्रांतों में नये गवर्नर नियुक्त किये हैं - नेपाल
- भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस बैंक पर ऋण नियमों का उल्लंघन करने पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है - मेहसाणा अर्बन - कोऑपरेटिव बैंक
- वह शिक्षण संस्थान जिसने भारत की पहली 'स्टैंडिंग व्हीलचेयर' बनाई है - आईआईटी मद्रास
- हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल ने जिस देश में दी जाने वाली निर्यात सब्सिडी पर आपत्ति जताई है - भारत
- वह भारतीय निशानेबाज जिसने हाल ही में दोहा में आयोजित एशियाई निशानेबाजी चौम्पियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल गेम में स्वर्ण पदक जीता है - मनु भाकर
- वह देश जिसने हाल ही में घोषणा की है कि वह भूमिगत संयंत्र के लिए यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेगा - ईरान
- आरबीआई ने हाल ही में मुंबई स्थित पंजाब ऐंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खातों की निकासी सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर जितने हजार रुपये कर दी - 50,000 रुपये
- हिंदी की जिस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिये चुना गया है - नासिरा शर्मा
- वह देश जिसने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है - चीन
- केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस संस्थान के लिए HS Code जारी किया है - खादी और ग्रामोद्योग आयोग
- हाल ही में जितने वैज्ञानिकों ने एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है - 11258
- फीफा 2020 अंडर - 17 महिला विश्व कप का आयोजन जिस देश में किया जायेगा - भारत
- हाल ही में जिस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हुई है - गुजरात
- प्रथम बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है - विशाखापत्तनम
- केंद्र सरकार ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु जितने करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है - 25,000 करोड़ रुपये
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जितने महीने के अंदर पराली जलाने का मुद्दा सुलझाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है - तीन महीने
- भारत और जिस देश ने हाल ही में बीमा क्षेत्र के विनियमन से संबंधित जानकारी के समन्वय, परामर्श और विनिमय हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये - अमेरिका
- हाल ही में सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, जिस देश में बेरोजगारी दर पिछले 3 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है - भारत
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने जिस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफार्म कार्यक्रम की शुरूआत की - आईबीएम
- जिस राज्य सरकार ने हाल ही में 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है - बिहार
- हाल ही में लैंड एंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन जिसे बनाया गया है - आदित्य मिश्रा
- वह देश जिसने बैंकॉक में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौतेः क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने का फैसला किया है - भारत
- हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जिस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली - गोवा
- शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को जिस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है - यूएई
- वह देश जिसके उपग्रह हायाबुसा-2 ने रायगु नामक क्षुद्रग्रह से पृथ्वी पर लौटने की यात्रा शुरू की है- जापान
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किये जाने वाले विकास कार्यों में जिस देश ने एक करोड़ 35 लाख डॉलर का सहयोग देने का संकल्प जताया है- भारत
- सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह मामला 7 जजों की बेंच को भेज दिया है- सबरीमला मंदिर
- वह भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम TIME 100 Next सूची में शामिल किया गया है- दुती चंद
- इसरो ने हाल ही में जिस मिशन के लिए 12 संभावित यात्रियों का चुनाव किया है- गगनयान मिशन
- यूनेस्को द्वारा जब से जब तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाये जाने की घोषणा की गई है- 19 से 25 नवंबर
- TRACE Bribery Risk Matrix के अनुसार दक्षिण एशिया के जिस देश में रिश्वत के लेन-देन का रिस्क सबसे अधिक है- बांग्लादेश
- हाल ही में जिस राज्य सरकार ने 'शिशु सुरक्षा' मोबाइल एप्प लॉन्च किया है- असम

हिमाचल सामान्य ज्ञान

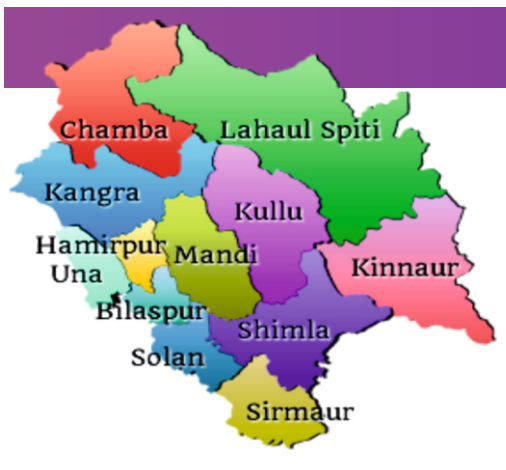

- किस दर्रे को शिंगो ला के नाम से जाना जाता है - जांस्कर पास
- निष्ठा कार्यक्रम जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है - शिक्षा
- हिमाचल के मुख्यन्यायाधीश लिंगपा नारायण स्वामी कौन से न्यायाधीश बने - 25
- रूकुमणी कुंड कहां पर स्थित है - बिलासपुर
- जलधार मंदिर कहां पर स्थित है - भरमौर में, बुधिल नदी के
- हाल ही में उड़ान मेला किसकी ओर से आयोजित किया गया था - नाबार्ड
- कुल्लू दशहरे में कितने वादकों ने एक साथ देवधुन बजाई थी - 2200
- गुरू गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की - मेदनी प्रकाश
- कांगड़ा के राजा विधिचंद ने सभी पहाड़ी शासको का संघ बनाकर कब अकबर के विरूद्ध युद्ध किया - 1588–89
- 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुल्लू रियासत के किस शासक को राय की उपाधि मिली थी - ज्ञान सिंह
- शिमला में पहली बार रेल कब पहुंची थी - 1906
- जनजातीय क्षेत्र की पहली पन विद्युत परियोजना कौन सी है - रोंगटोंग पन विद्युत परियोजना-2 मेगावाट
- बार्नस कोर्ट को कब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान घोषित किया गया - 1992
- हिमाचल प्रदेश क्षेत्रिय परिषद को विधान परिषद में कब परिवर्तित किया गया - 1 जुलाई 1963 को
- प्राचीन काल में किन्नौर राज्य के दो प्रमुख व्यापार केंद्र कौन से थे - सांगला और रामपुर
- कसौली के समीप सनावर स्थित लारेंस स्कूल की स्थापना कब हुई थी - 1847
- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टैक्नॉलॉजी (सीपेट) कहां पर स्थित है - बद्दी
- बस्पा बैली के मुहाने पर कौन सा दर्रा अवस्थित है - चुग संखांगो
- कमरू और सपनी फोर्ट कहां पर है - सांगला वैली
- किन्नौर का आखरी गांव कौन सा है - छितकुल 711319 फीट
- ओरामिंग मंदिर कहां पर स्थित है - किन्नौर में
- चंपा और छेशिम कहां का लोकनृत्य है - किन्नौर का
- कहां पर गांव को देशांग कहा जाता है - किन्नौर में
- कमीलागा पास किसे किन्नौर से जोड़ता है - गढ़वाल
- चंगीरजंग गर्मपानी का चश्मा कहां पर है - किन्नौर
- लिप्पा, जांगी, छांगो और कानम मोनास्ट्री कहां पर है - किन्नौर में
- परासला चोटी कहां पर है - किन्नौर
- रोहतांग को और किस नाम से जाना जाता है- भृगु तुंग
- हिमाचल में वनो के अधीन भूमि -
- 66.52 प्रतिशत
- चाय की खेती -2310 हैक्टेयार , 1850 में कांगड़ा
- हिमाचल के किस शहर को हैरीटेज सीटी का दर्जा दिया गया था - मंडी को
- पुराने हिमाचल में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है - 48.4 प्रतिशत

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरू आत की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना रखा गया है। यह योजना खेतों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत खेतों की संरक्षण के लिए सौर फेंसिंग लगवाई जाएगी। इसके लिए सरकार 85 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है।

यह सब्सिडी 3 या उससे अधिक समूह के किसानों को मुहैया करवाई जाती है। आए दिन खेतों को जानवर बर्बाद कर देते हैं जिससे कि फसल का बहुत नुकसान हो जाता है। सोलर फेंसिंग की मदद से किसान अपने खेतों और उसमें लगी हुई फसल को बचा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत खेत के चारों तरफ सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि विभाग में जाकर सोलर बाढ़ लगाने के लिए 15 प्रतिशत हिस्सा ही जमा करना होगा। इसका कारण यह है कि 85 प्रतिशत खर्चा सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। पहले किसानों को 20 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन अभी राशि और भी घटकर 15 प्रतिशत कर दी गई है क्योंकि सरकार ने सब्सिडी को 80 से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है।

यह खेत संरक्षण योजना सब्सिडी सरकार तब मुहैया करवाएगी जब 3 या उससे अधिक किसान समूह में आकर इस योजना के लिए आवेदन करेंगे। इस योजना को अच्छी तरह से लागू करने के लिए इस साल सरकार ने 35 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि इस योजना के लाभ, जरूरी कागजात, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में हम द रीव टाइम्स के इस अंक में जानकारी दे रहे हैं।

योजना का नाम	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
पात्र	हिमाचल के किसान
बजट	33 करोड़ रुपए का
पात्रता	3 या उससे अधिक किसानों का समूह बनाकर आवेदन
सब्सिडी	85 प्रतिशत

इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 32 कंपनियों को सोलर फेंसिंग लगाने के लिए चुना है। जैसे ही किसान आवेदन करते हैं यह कंपनियां आकर उनके खेतों में फेंसिंग लगा जाती है। इस योजना का मकसद जानवरों से होने वाली फसल के नुकसान को कम करना है। इस योजना के तहत सोलर फेंसिंग 1500 मीटर की रनिंग तार लगाई जाएगी, जो खेतों के चारों तरफ होगी। इसके लिए करंट सोलर प्लांट द्वारा जनरेट किया जाएगा। इसके लिए सोलर प्लांट भी विस्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अब किसान चुनी गई कंपनियों में से अपनी पसंद की कंपनी को आवेदन करके सेंसिंग लगवा सकता है। अगर किसान को किसी कंपनी का काम पसंद नहीं आता वह दूसरी कंपनी की तरफ जा सकता है।

खेत संरक्षण योजना सोलर के लिए सब्सिडी – 85 प्रतिशत

जो किसान अकेले आवेदन करवाना चाहते हैं उन्हें 80 प्रतिशत तक का सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लाभ उठाने के लिए किसानों को जिला कृषि खंड में जाकर आवेदन करना होगा। जब योजना शुरू की गई थी तब किसानों को 60 रू 40 के अनुपात में अनुदान मिलता था। इसकी वजह से किसान को फेंसिंग करवाने में काफी खर्च करना पड़ता था। इस वजह से यह योजना किसानों में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन अब अनुदान राशि 80 से 85 प्रतिशत कर देने के कारण किसानों में इस योजना के प्रति दिलचस्पी दिखाई दे रही है।

तीन तरह की फेंसिंग

इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार की जाती है। किसान अपने मनपसंद के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी प्रकार की फेंसिंग को चुन सकता है। यह तीन प्रकार की फसल किस प्रकार से है-

- पांच फीट की ऊंची फेंसिंग
- सात फीट की ऊंची फेंसिंग
- नौ फीट की ऊंची फेंसिंग
- **सोलर फेंसिंग योजना के लाभ**
- इस योजना से जानवर द्वारा फसल का किया जाने वाला नुकसान कम हो पाएगा।
- इसे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- प्रदेश में फसल की पैदावार में वृद्धि होगी।

हिमाचल प्रदेश खेत संरक्षण योजना

खेत संरक्षण योजना मुख्यमंत्री ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बागवानी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस बारे में अधिक जानकरी बागवानी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती हैं।

गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515

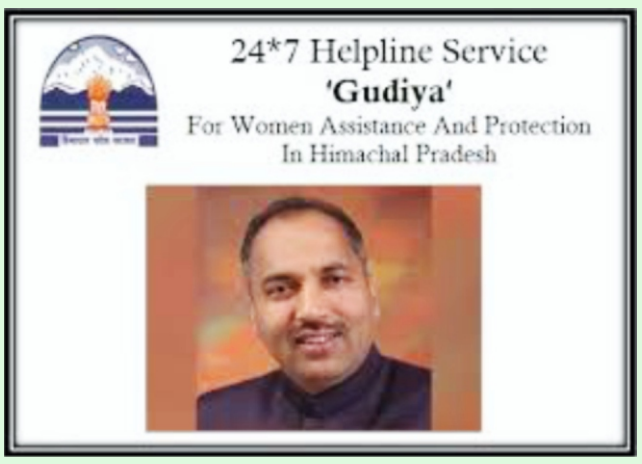

हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में एक शांत राज्य के तौर पर जाना जाता है। लेकिन 2017 में हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में एक बहुत ही बुरी घटना घटी थी। इस घटना में कोटखाई की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद बेहद निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर आ गई थी। प्रदेश में महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया था।

इस घटना के तुरंत बाद राज्य में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को भारी मतों से विजय मिली। नई सरकार ने हिमाचल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए "गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515" की शुरूआत की। इसके साथ ही राज्य में क्राइम को रोकने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन 1090 भी शुरू की गई। इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 7 से 8 हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं। यह हेल्पलाइन नंबर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जारी किए गए हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद, बहुत सी हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। इन सभी हेल्पलाइनो की सूची हम आपको नीचे देने जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से गुड़िया हेल्पलाइन नंबर 1515 को जारी किया गया है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1091 भी चल रही है।

गुड़िया हेल्पलाइन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ रही छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को परेशान अथवा कोई भी कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वह इस गुड़िया हेल्पलाइन 1515 कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। उसके द्वारा दर्ज करवाई की शिकायत उनके नजदीकी थाना को भेजी जाएगी जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल और पहले से ही एक शांतिपूर्ण रहा है। लेकिन पिछले कुछ राज्य में हुई बहुत ही और बुरी घटनाओं से, राज्य का माहौल खराब हुआ है। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को यह कदम उठाने पड़े हैं। इस सूची को नीचे विस्तार से बताया गया है। इस सूची की मदद से, आप कभी भी इन हेल्पलाइन नंबरों को देखकर डायल कर सकती हैं।

गुड़िया हेल्पलाइन : 1515

होशियार हेल्पलाइन : 1090

हिमाचल प्रदेश मुख्य हेल्पलाइन नंबर सूची

गुड़िया हेल्पलाइन नंबर	1515
महिला हेल्पलाइन नंबर	1091
होशियार सिंह हेल्पलाइन	1090
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
मेडिकल चिकित्सा हेल्पलाइन	102 एवं 108
पुलिस हेल्पलाइन	100
आपदा प्रबंधान हेल्पलाइन - टोल फ्री नंबर	1077
फायर ब्रिगेड नंबर	101
एंटी करप्शन विभाग - भ्रष्टाचार के खिलाफ रिपोर्ट हेतु हेल्पलाइन	0177-2629813
साइबर सेल हिमाचल प्रदेश हेल्पलाइन	0177-2621714

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

देश में छोटे और मध्यम आकार के उद्योग शुरु करने से जुड़ी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की थी। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको इस योजना की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं।

मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो इकाइयां विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड है इसे NCSBS संगठन के रुप में जाना जाता है। यह गैर कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय के क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करता है। इस लक्ष्य के साथ मुद्रा को सिडबी की एक सहायक कंपनी के रुप में स्थापित कर शुरु किया गया है। योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला– स्वरोजगार के लिए आसान लोन उपलब्ध करवाना और दूसरा– छोटे उद्यमों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सामने लाना। यह लोन नॉन–कॉर्पोरेट छोटे व्यवसायों के लिए बनाया गया है, इसलिए मुद्रा लोन शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले या पार्टनरशिप में छोटी निर्माण यूनिट चलाने वालों से लेकर दुकानदारों, छोटा व्यवसाय/व्यापार करने वालों, छोटी इंडस्ट्रीज चलाने वालों, कारीगरों, खाद्य उत्पादों से जुड़ा व्यापार करने वालों और सर्विस सेक्टर में काम करने वालों तक के काम की योजना है। ये लोन वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे फाइनेंस बैंकों, सहकारी बैंकों, माइक्रोफाइनेंस (सूक्ष्म–वित्त) संस्थानों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आवेदन देकर पाया जा सकता है।

मुद्रा लोन से जुड़े चार प्रमुख सवाल

- कितना लोन मिल सकता है?

मुद्रा लोन के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। इस लोन को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है– शिशु ऋण, जिसमें अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए है, किशोर ऋण, जिसमें 50 हजार से 5 लाख रुपए तक की सीमा है और तरुण ऋण, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सीमा रखी गई है।

- किसे मिल सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरु करना चाहता है, वह इस योजना के तहत लोन ले सकता है। इसके साथ ही अगर कोई अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है, तो भी उसे इस योजना के माध्यम से लोन मिल सकता है।

- कैसे ले सकते हैं?

मुद्रा लोन के लिए उस सरकारी या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान में आवेदन देना होगा, जो मुद्रा लोन देता हो। आवेदन के लिए आपके कारोबार की पूरी जानकारी/प्लान सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

- कितना ब्याज देना होगा?

मुद्रा लोन की खास बात यह है कि इसमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। अलग–अलग बैंक लोन पर अलग–अलग दर से ब्याज वसूल सकते हैं। दर का निर्धारण कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय होता है। वैसे सामान्यतः ब्याज दर 12 प्रतिशत के आसपास रहती है।

फर्मों के प्रकार जो आवेदन कर सकते हैं :–

किसी भी प्रकार के फर्म चाहे वह स्वामित्व या साझेदारी हो जो एक गैर

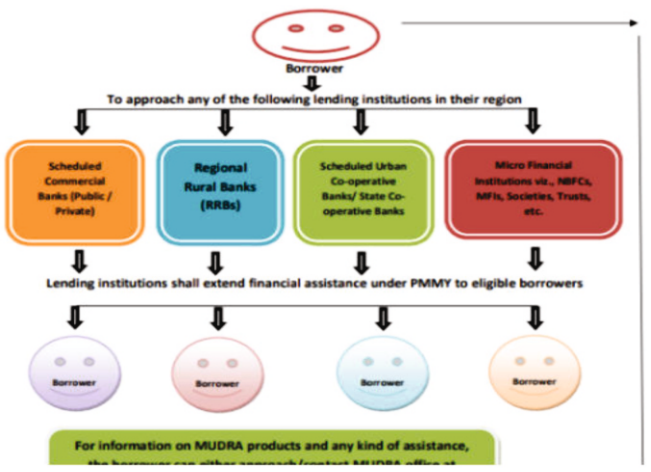

कॉर्पोरेट छोटे व्यवसाय के (NCSB) दायरे में आता है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। NCSB एक ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कहीं भी हो सकता है। जैसे कि:

- एक सेवा क्षेत्र की इकाई
- एक विनिर्माण इकाई
- एक खाद्य सेवा / खाद्य प्रसंस्करण इकाई
- एक छोटी औद्योगिक इकाई
- एक फल या सब्जी विक्रेता
- एक दुकानदार (आप भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए यदि आप एक मताधिकार आउटलेट खोलने की इच्छा रखते हैं)
- एक ट्रक ऑपरेटर
- एक कारीगर

एक महिला उद्यमी भी महिला उद्यमी योजना के तहत इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जो मुद्रा का हिस्सा है सभी महिला उद्यमी को 3 मुद्रा ऋण श्रेणियों, तरुण, किशोर तथा शिशु के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुद्रा के लिए पात्रता मानदंड

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण देने के लिए पुनर्वित्त / वित्त लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए साथी ऋण संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए

- आपका निरंतर तीन साल का लाभ रिकॉर्ड किसी सार्वजनिक / निजी क्षेत्र में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में होना चाहिए।
- आपका नेट एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य और सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए

- आपका एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 3 प्रतिशत के भीतर नेट एनपीए होना चाहिए (इससे पात्र मामलों में छूट दी जा सकती है) सीआरएआर 9 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।

- एमएफआई / लघु व्यापार वित्त कंपनियों / एनबीएफसी
- एक सूक्ष्म इकाई को 10 लाख रुपए तक के ऋण को न्यूनतम 3 साल के लिए देने के लिए, यूनिट के प्रवर्तक / प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए।
- आप मौजूदा एमएफआई के लिए 3000 ऋण लेने वालों की एक न्यूनतम पहुंच से बाहर होने चाहिए।
- आपको उचित अपेक्षित लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन, नकदी प्रबंधन, एमआईएस और जगह में अन्य प्रक्रियाओं होना चाहिए।
- आपको न्यूनतम सीआरएआर और अन्य मानदंडों एनबीएफसी–एमएफआई के रूप में पंजीकृत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप एमएफआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
- आपको एक क्रेडिट ब्यूरो का सदस्य होना चाहिए।

महत्वपूर्ण पैरामीटर जो सभी के लिए सहायता का निर्धारण करेगा

- MUDRA / सिडबी द्वारा एक आंतरिक ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया।
- जोखिम मूल्यांकन, भौगोलिक वितरण, सामाजिक मानक आदि मुद्रा बोर्ड उधारकर्ताओं के विभिन्न श्रेणियों के लिए उधार देने के लिए विवेकपूर्ण कर देंगे। यह सीमा भी एक व्यक्ति को ऋण लेने के लिए / उधारकर्ताओं के एक समूह को भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार

- सहायता के विस्तृत नियम ऋण समझौते में निर्धारित किया जाएगा व्यक्ति मध्यस्थ के साथ क्रियान्वित किया जाना है।
- http://www.mudra.org.in/eligibility-criteria.pdf पात्रता आवश्यकताओं का पूरा विवरण यहां उपलब्ध है।

मुद्रा कार्ड

एक पूर्व लोड मुद्रा कार्ड भी उपकरणों, कच्चे माल और पंजीकृत उत्पादकों से या ऑनलाइन साधनों के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध हो जाएगा। इस कार्ड पर क्रेडिट सीमा, उद्यम के लिए मंजूर ऋण सीमा का 20 प्रतिशत होगा। एक कार्ड पर 10,000 रूपये की अधिकतम ऋण सीमा के साथ किया जा रहा है। प्रिंसिपल जारीकर्ता होगी मुद्रा और कार्ड पोर्टफोलियो का 20 प्रतिशत होगा तक का जोखिम मुद्रा के रूप में ऋण

गारंटी योजना के तहत कवर किया जाएगा। शेष जोखिम एमएफआई सहयोगियों के साथ बने रहेंगे। इसके अलावा एक सुविधा को बाद में जोड़ने के लिए आपका (उधारकर्ता) मुद्रा कार्ड बनाया जा सकता है।

यह है मुद्रा लोन पाने की पूरी प्रक्रिया

पहला चरण–

सबसे पहले आवेदक को एक बिजनेस प्लान तैयार करना होता है। साथ ही लोन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज भी तैयार करने होते हैं। सामान्य दस्तावेजों के साथ बैंक आपसे आपका बिज़नेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भविष्य की आय के अनुमान संबंधी दस्तावेज भी मांगेगा, ताकि उसे आपकी आवश्यकता की जानकारी हो, साथ ही यह भी अंदाजा लग सके कि आपको लाभ कैसे होगा या लाभ कैसे बढ़ेगा।

दूसरा चरण–

मुद्रा लोन देने वाले बैंक/वित्तीय संस्था का चयन करना होता है। आवेदक एक से अधिक बैंकों का चयन कर सकता है। बैंक को दस्तावेजों के साथ लोन एप्लिकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। किस तरह के बैंक/संस्था न मुद्रा लोन देते हैं, इसकी जानकारी ऊपर दी गई है।

तीसरा चरण

आवेदन सही पाए जाने पर बैंक या वित्तीय संस्थान मुद्रा लोन पास करेगा और आवेदक को मुद्रा कार्ड प्रदान किया जाएगा।

मुद्रा योजना के चार बड़े फायदे

- इस योजना के तहत बिना गारंटी के लोन लिया जा सकता है।
- इसके लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं चुकानी पड़ती।
- लोन भुगतान अवधि को पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- लोन लेने वाले को मुद्रा कार्ड दिया जाता है, जिस का उपयोग कारोबारी जरूरत पर आने वाले खर्च के लिए कर सकता है।
- जरूरी दस्तावेज़ (डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट)
- सामान्यतः मुद्रा लोन के लिए आपको आवेदन फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। ऋण की राशि , व्यापार की प्रकृति ,

mudra

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लिए हेल्प कंप्लेंट नंबर , लाइन नंबर , टोल फ्री नंबर , कांटेक्ट डिटेल्स

www.techuhelp.com

बैंक नियमों आदि के आधार पर दस्तावेज़ों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।

- मुद्रा लोन आवेदन, बिज़नेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पहचान संबंधी दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड , आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र आदि । एक से ज्यादा आवेदकों की स्थिति में पार्टनरशिप संबंधी दस्तावेज़ (डीड), टैक्स रजिस्ट्रेशन, बिज़नेस लाइसेंस आदि । निवास के प्रमाण संबंधी दस्तावेज़, जैसे टेलीफोन बिल/बिजली बिल आदि आवेदक की 6 महीने से कम पुरानी तस्वीरें, मशीन या अन्य सामग्री का कोटेशन जिसे खरीदना चाहते हैं, साथ ही जहां से खरीदेंगे उस सप्लायर/ दुकानदार के बारे में जानकारी, श्रेणियां(एस सी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक), अगर लागू हो तो पिछले दो वर्षों की बैलेंस शीट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट (दो लाख से ऊपर के लोन पर)।

सेब उत्पादन से जुड़ी कोई समस्या है तो मिशन रीव करेगा समाधान

सेब उत्पादकों को एक साथ लाने में कर रहा मदद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मिशन रीव हिमाचल में किसानों और बागवानों के लिए कृषक मित्र के तौर पर हर समस्या का निदान करने का कार्य कर रहा है। खास बात यह है कि किसानों -बागवानों की समस्या के बारे में जानने के लिए मिशन रीव खुद उनके गांव-घर पहुंच रहा है। मिशन रीव के तहत विषय विशेषज्ञों को साथ लेकर मिशन रीव की टीम बागवानों के लिए खासतौर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में नामी सेब उत्पादकों, विशेषज्ञों को साथ लेकर बागवानों को बेहतर सेब उत्पादन की जानकारी दी जा रही है। हाल ही में ऊपरी शिमला की विभिन्न पंचायतों बागवानों के लिए खासतौर पर

जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। छोहारा ब्लॉक के तहत खरशाली में आयोजित जागरूकता शिविर में करीब 50 किसान-बागवानों ने भाग लिया। इस शिविर

में बागवानों को सेब उत्पादन से जुड़ी सभी विधियों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मिट्टी परीक्षण और इसके महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

इसी तरह जुब्बल के तहत दोची में भी जागरूकता शिविर में बागवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और सेब उत्पादन में आ रही समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया। सेब के व्यापार और उसे सही समय पर मंडी तक पहुंचाने के बारे में भी बात की गई। रोहडू के डिस्वानी में आयोजित जागरूकता शिविर में विशेष तौर पर सेब उत्पादकों की समस्याओं के निदान को लेकर चर्चा की गई।

इन शिविरों के आयोजन में मिशन रीव के प्रतिनिधि पंकज चौहान, गौरव, राहुल और रमेश ने सहयोग दिया। मिशन रीव के इन प्रतिनिधियों ने बताया कि शिविर के दौरान बागवानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें विशेषज्ञ सलाह भी दी गई। शिविर में उन उत्पादकों न भी हिस्सा लिया जो सेब उत्पादन के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं। इन उत्पादकों ने भी सेब उत्पादन को लेकर अपने विचार साझा किए।

ग्रेडिंग और होमलोन की भी सुविधा

जो किसान एप्पल ग्रेडिंग मशीन लगाना चाहते हैं अथवा होम लोन व किसी भी तरह का अन्य लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी मिशन रीव की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। हाल ही में होमिंद्र, यशवंत, ललित, लायक राम और रविंद्र के इसी तरह के लोन केस मिशन रीव की ओर से पूरे किए जा रहे हैं। लोन लेने से जुड़ी तमाम तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने में मिशन रीव सहयोग देता है। इसके अलावा ग्रेडिंग मशीन के लिए लोन लेने से लेकर मशीन इंस्टॉल करने तक मिशन रीव की ओर से सहयोग किया जाता है।

बहरहाल मिशन रीव आज प्रदेश के किसानों और बागवानों के बीच एक विशेष पहचान बना चुका है और एक सहयोगी के तौर पर लोगों को उनके घर-द्वार पर विभिन्न तरह की सुविधाएं पहुंचा रहा है।

व्हट्सअप ग्रुप पर समस्याओं का समाधान

किसानों-बागवानों की समस्याओं का तुरंत निदान करने और विशेषज्ञों की राय से अवगत कराने के लिए मिशन रीव के तहत किसानों -बागवानों और बागवानी विशेषज्ञों का एक व्हट्सअप ग्रुप बनाया गया है। इसमें अभी तक तीन सौ से अधिक सदस्य हैं।

कोई भी बागवान इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप अंकुश नगरैक के मोबाईल नंबर **98167-41687** अथवा पंकज चौहान के मोबाईल नंबर **70186-93145** पर संपर्क कर सकते हैं। मिशन रीव के अतिरिक्त कार्यक्रम प्रबंधक अंकुश नगरैक ने बताया कि इस ग्रुप के माध्यम से अभी तक सैंकड़ो बागवान लाभ ले चुके हैं। नगरैक ने बताया कि जागरूकता शिविर के माध्यम से भी बागवानों को सेब उत्पादन से जुड़ी बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जा रही है।

द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा

प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.

द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

संपादक: हेम राज चौहान

फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021
E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org